3 कटरा वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन का खतरा, प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया

84 रन छक्के–चौके से मारे, सिर्फ इतनी गेंदों में जमाया शतक, ऐसा करने वाले तीसरे बल्लेबाज बने कृष्णा 8

मौसम

अधिकतम तापमान- 32
न्यूनतम तापमान- 26

सर्राफा

सोना प्रति 10 ग्राम- 93950
चांदी प्रति किलोग्राम- 1,25,000

ई–पेपर के लिए लॉग ऑन करें-: http://raftarsamachar.org/

दैनिक
रफ़्तार समाचार
राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र

वर्ष 14 | अंक 217 | पृष्ठ : 8 | मूल्य : 3 रुपये जम्मू व कश्मीर, वीरवार, 04 सितंबर 2025 आरएनआई न.: JKHIN/2011/38527

दूध छेना, पनीर पर कोई टैक्स नहीं

मोदी सरकार का जीएसटी पर बड़ा कदम: 12-28% स्लैब खत्म, अब सिर्फ 5 और 18%

रफ्तार समाचार ब्यूरो

नई दिल्ली 3 सितंबर: जीएसटी को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा परिवर्तन किया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 12 और 28 फीसदी का टैक्स स्लैब खत्म करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही सिर्फ पांच फीसदी और 18 फीसदी के टैक्स लागू होंगे। इसके बाद दैनिक जरूरत की चीज सस्ती हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर कहा कि इसका मकसद आम आदमी को राहत देना है। परिषद ने तम्बाकूऔर विलासिता की वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत की नई स्लैब को मंजूरी दी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ''हमने स्लैब कम कर दिए हैं। अब केवल दो स्लैब होंगे और हम क्षतिपूर्ति उपकर के मुद्दों पर भी विचार कर रहे हैं।'' सीतारमण ने कहा कि ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। आम आदमी के दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले हर कर की कड़ी समीक्षा की गई है और ज्यादातर मामलों में दरों में भारी कमी आई है... श्रम प्रधान उद्योगों को अच्छा समर्थन दिया गया है। किसानों और कृषि क्षेत्र के साथ–साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ होगा। अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालकों को प्रमुखता दी जाएगी।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि आम आदमी और मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर जीएसटी पूरी तरह से कम कर दिया गया है। जिन वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है, वे हैं हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान। जिन वस्तुओं पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है, वे हैं अल्ट्रा–हाई टेम्परेचर दूध, छेना और पनीर। सभी भारतीय रोटियों पर जीएसटी शून्य होगा। यानी रोटी हो या पराठा, सब पर शून्य। जीएसटी 12% से घटाकर 18% या 5% कर दिया गया है –

खाद्य पदार्थ – नमकीन, बुज्जिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी, ये सभी 5% के दायरे में हैं।

28% से घटाकर 18% – एयर कंडीशनिंग मशीनें, 32 इंच से बड़े टीवी, सभी टीवी अब 18%, डिशवाशिंग मशीनें, छोटी कारें, 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलें, सभी पर अब 18% कर लगेगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ''33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से घटकर शून्य हो गया है।'' वह यह भी कहती हैं कि कृषि उत्पाद जैसे ट्रैक्टर, मिट्टी तैयार करने या खेती के लिए कृषि, बागवानी और वानिकी मशीनें, कटाई या थ्रेसिंग मशीनें, जिनमें पुआल या चारा बेलर, घास या भूसा मूवर, खाद बनाने की मशीनें आदि शामिल हैं, सभी पर कर की दर 12 से घटकर 5% हो गई है। 12 निर्दिष्ट जैव–कीटनाशकों पर

शेष भाग पृष्ठ 2 पर

उपराज्यपाल ने स्थिति का जायजा लिया, राजौरी में हुई त्रासदी पर शोक व्यक्त किया

रफ्तार समाचार ब्यूरो

श्रीनगर, 3 सितंबर: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर में अत्यधिक वर्षा के मद्देनजर स्थिति का जायजा लिया। उन्हें भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेना, वायु सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, जिला प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों द्वारा किए जा रहे बचाव और राहत कार्यों की जानकारी दी गई।

उन्हें बताया गया कि अखनूर में बाढ़ प्रभावित लोगों को बीएसएफ, एनडीआरएफ और पुलिस द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। अनंतनाग, बडगाम और पुलवामा के लगभग 67 गाँवों

शेष भाग पृष्ठ 2 पर

कश्मीर विश्वविद्यालय और क्लस्टर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित

रफ्तार समाचार ब्यूरो

श्रीनगर, 3 सितंबर: कश्मीर विश्वविद्यालय और क्लस्टर विश्वविद्यालय श्रीनगर के परीक्षा नियंत्रक ने बुधवार को आदेश दिया कि 4 सितंबर, 2025 को होने वाली सभी परीक्षाएँ प्रतिकूल मौसम के कारण पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित नहीं की जाएँगी।

एक आधिकारिक सूचना में कहा गया है, ''खराब मौसम को देखते हुए, 04.09.2025 को होने वाली सभी विश्वविद्यालय परीक्षाएँ स्थगित कर दी गई हैं। स्थगित परीक्षाओं की नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी।''

क्लस्टर विश्वविद्यालय श्रीनगर ने भी इसी तरह का एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया है: ''खराब मौसम को

शेष भाग पृष्ठ 2 पर

जम्मू–कश्मीर को 190 अतिरिक्त एमबीबीएस सीटें मिली

रफ्तार समाचार ब्यूरो

श्रीनगर, 3 सितंबर: जम्मू–कश्मीर में चिकित्सा शिक्षा को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने आज केंद्र शासित प्रदेश के पाँच सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 190 अतिरिक्त एमबीबीएस सीटों के लिए अनुमति पत्र (एलओपी) जारी किए हैं।

इन स्वी.तियों में सरकारी मेडिकल कॉलेज बारामूला, सरकारी मेडिकल कॉलेज डोडा और सरकारी मेडिकल कॉलेज कठुआ, प्रत्येक के लिए 50 अतिरिक्त सीटें शामिल हैं, जबकि सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू और सरकारी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर को 20–20 सीटें आवंटित की गई

शेष भाग पृष्ठ 2 पर

बीडीओ समेत तीन अधिकारियों को अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए कारण बताओ नोटिस जारी

रफ्तार समाचार ब्यूरो

जम्मू, 3 सितंबर: जम्मू–कश्मीर के रियासी जिले में एक खंड विकास अधिकारी और एक सहायक कार्यकारी अभियंता समेत तीन अधिकारियों को सरकारी निर्देशों के विपरीत ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने 27 अगस्त को स्पष्ट रूप से कहा था कि क्षेत्र में खराब मौसम और लगातार बारिश के कारण किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को छुट्टी

शेष भाग पृष्ठ 2 पर

चिनाब नदी उफान पर, अखनूर के कई गांव जलमग्न, 40 फंसे, बचाव कार्य जारी

जम्मू में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई, माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित

कारगिल में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, स्कूल बंद, राजमार्ग बंद

कारगिल में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, स्कूल बंद, राजमार्ग बंद

ताजा भूस्खलन से जोजिला मार्ग बंद, यातायात बाधित

रवि कुमार

कटरा/जम्मू/कारगिल, 3 सितंबर: अधिकारियों ने कहा कि त्रिकुटा पहाड़ियों के ऊपर माता वैष्णो देवी मंदिर की तीर्थयात्रा बुधवार को नौवें दिन भी स्थगित रही क्योंकि आधार शिविर कटरा में पिछले 24 घंटों के दौरान 200 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई – जो जम्मू क्षेत्र में सबसे अधिक है।

26 अगस्त को मंदिर की यात्रा स्थगित कर दी गई थी, कुछ घंटे पहले बारिश के कारण हुए एक बड़े भूस्खलन ने

अर्धकुंवारी के पास पुराने मार्ग को प्रभावित किया और 34 तीर्थयात्रियों की जान ले ली और 20 अन्य घायल हो गए। हालांकि तीर्थयात्रा स्थगित है, मंदिर स्वयं खुला है और इसके पुजारी दैनिक प्रार्थना और अनुष्ठान कर रहे हैं। यात्रा रद्द होने के साथ, कटरा पहुंचे कुछ तीर्थयात्री 'दर्शनी ड्योढ़ी' (मंदिर के रास्ते में मुख्य प्रवेश द्वार) पर पूजा कर रहे हैं। दर्शनी ड्योढ़ी मंदिर के पहले 'दर्शन' का प्रतिनिधित्व करती

शेष भाग पृष्ठ 2 पर

वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जम्मू–कश्मीर के रियासी में बारिश से प्रभावित 1,000 परिवारों की मदद की

रफ्तार समाचार ब्यूरो

जम्मू, 3 सितंबर: मानवीय . ष्टिकोण से, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ें(डटकैठ) ने कटरा और रियासी और उधमपुर जिलों के आसपास के इलाकों में भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित 1,000 से अधिक परिवारों का समर्थन करने के लिए एक महत्वपूर्ण राहत पहल की है।

शेष भाग पृष्ठ 2 पर

हिमाचल में भारी बारिश: भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 7 हुई, सड़कें और स्कूल बंद

शिमला, 3 सितंबर: हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण फिर से तबाही मची है। बचाव कर्मियों ने मंडी जिले में भूस्खलन के मलबे से चार और शव बरामद किए हैं, जबकि कुल्लू जिले में दो मकान ढहने से एनडीआरएफ के एक जवान समेत दो लोगों के मारे जाने की आशंका है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

शेष भाग पृष्ठ 2 पर

जम्मू में उच्च जोखिम वाले बचाव अभियान में बीएसएफ के हेलीकॉप्टरों ने 45 फंसे ग्रामीणों को बचाया

जम्मू, 3 सितंबर: सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने बुधवार को एक साहसिक अभियान के तहत अपने हेलीकॉप्टर से अखनूर सेक्टर के बाढ़ग्रस्त गाँव में फंसे महिलाओं और बच्चों समेत 45 नागरिकों को निकालने के लिए एक उच्च जोखिम वाला बचाव अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि

बीएसएफ ने यह बचाव अभियान तब शुरू किया जब पुलिस, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की टीमें गरखल इलाके के फतहू कोटली गाँव की बाढ़ग्रस्त आबादी को निकालने में विफल रहीं। चिनाब नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और यह नदी अपने निकासी स्तर 42 फीट से कई फीट ऊपर बह रही है।

उन्होंने बताया कि बाढ़ का पानी गाँव में घुसने और 45 लोगों के फँस जाने की सूचना मिलने पर आज सुबह वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचे।

फँसे हुए नागरिकों से संपर्क स्थापित करने के कई प्रयास

शेष भाग पृष्ठ 2 पर

मोदी सरकार का जीएसटी पर बड़ा कदमः 12-28% स्लैब खत्म, अब सिर्फ 5 और 18%

जीएसटी 12% से घटकर 5% हो गया है। इसके अलावा, 12 से 5ः में प्राकृतिक मेन्थॉल है... पुनः, 12 से 5ः में हस्तशिल्प और श्रम–प्रधान क्षेत्र भी शामिल हैं। वे क्या हैं? हस्तशिल्प, संगमरमर, ट्रैवर्टीन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक और चमड़े के मध्यवर्ती उत्पाद। सीमेंट पर जीएसटी 28ः से घटाकर 18ः कर दिया गया है। 33 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12ः से घटाकर शून्य कर दिया गया है। कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर पुरानी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 5 से 0 और 3 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12ः से घटाकर 5ः कर दिया गया है। कई दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12ः से घटाकर 5ः कर दिया गया है... इसी तरह, दृष्टि सुधार के लिए चश्मे और गॉगल्स पर भी जीएसटी 28ः से घटाकर 5ः कर दिया गया है।

निर्मला सीतारमण ने कहा, ''350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28ः से घटाकर 18ः कर दिया गया है।''

बसों, ट्रकों और एम्बुलेंस पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। सभी ऑटो पार्ट्स पर 18% की एक समान दर लागू की गई है। तिपहिया वाहनों पर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। मानव निर्मित वस्त्र क्षेत्र में लंबे समय से लंबित उलटे शुल्क ढांचे की समस्या का समाधान मानव निर्मित रेशे पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% और मानव निर्मित धागे पर 12% से घटाकर 5% करके किया जा रहा है।

हम सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% करके उर्वरक क्षेत्र में उलटे शुल्क ढांचे की समस्या का भी समाधान कर रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और उनके निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले भागों जैसे बायोगैस संयंत्र, पवन चक्कियां, पवन ऊर्जा से चलने वाले विद्युत जनरेटर, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र, उपकरण, पी.वी. सेल, चाहे वे मॉड्यूल में संयोजित हों या पैनल में बने हों, सौर कुकर, सौर जल हीटर और प्रणालियां आदि पर जीएसटी को 12 से घटाकर 5% किया गया है।

सीतारमण कहती हैं, ''एक विशेष दर है जो 40% है। लगभग सभी सामान 18% से 5% के बीच हैं। एक विशेष दर है जो केवल सिन और सुपर लक्जरी वस्तुओं के लिए है। 40% की विशेष दर भी प्रस्तावित की गई है, और इसे मंजूरी दे दी गई है और यह केवल पान मसाला, सिगरेट, गुटका और अन्य तंबाकू उत्पादों जैसे चबाने वाले तंबाकू, जर्दा, अनिर्मित तंबाकू और बीड़ी जैसे उत्पादों पर लागू होगी।'' सभी वस्तुएं, जिनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ युक्त वातित जल या स्वादयुक्त, कैफीनयुक्त पेय, फलों के पेय के कार्बोनेटेड पेय या फलों के रस के साथ कार्बोनेटेड पेय और अन्य गैर–अल्कोहलिक पेय शामिल हैं, कम दरों पर निर्दिष्ट वस्तुओं को छोड़कर, सभी 40% के अंतर्गत कवर किए जाएंगे।

जम्मू में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई, माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित

है। महाराष्ट्र के नागपुर से आए एक श्रद्धालु प्रमोद ने पीटीआई–भाषा को बताया, ''मैंने मंदिर में पूजा–अर्चना के लिए लगभग तीन महीने पहले अपनी उड़ान, ट्रेन और होटल की टिकटें बुक कर ली थीं। लेकिन तीर्थयात्रा स्थगित है, इसलिए मैं घर लौटने से पहले यहीं (दर्शनी ड्योढ़ी) से पूजा–अर्चना कर रहा हूँ।'' हालाँकि, उन्होंने कहा कि वे निराश नहीं हैं और उन्होंने वापस लौटने और ''माता के बुलावे का इंतजार'' करने का संकल्प लिया है। लगातार बारिश के कारण नदियों और नालों, खासकर शहर से होकर गुजरने वाली बाणगंगा नदी, का जलस्तर बढ़ गया है। अधिकारियों ने कहा कि यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला तब लिया जाएगा जब हालात सुधर जाएँगे और पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक जाने वाला 12 किलोमीटर का दोहरा रास्ता श्रद्धालुओं के लिए साफ हो जाएगा।

पिछले 20 घंटों से लगातार हो रही बारिश, जिसमें पिछले 24 घंटों में 28 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, ने कारगिल में सामान्य जनजीवन अस्त–व्यस्त कर दिया है।

मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है, जबकि जिला प्रशासन ने एक दिन के लिए सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है और निवासियों से सतर्क रहने और आपात स्थिति में नियंत्रण कक्ष से संपर्क करने का आग्रह किया है।

खराब मौसम के कारण कारगिल–लेह राजमार्ग बंद रहने के कारण पुलिस भी लोगों से बाहर न निकलने की अपील कर रही है।

लगातार बारिश के बाद बुधवार को जम्मू संभाग के अखनूर इलाके में चिनाब नदी खतरे के निशान को पार कर गई, जिससे एक मंदिर जलमग्न हो गया और क्षेत्र के कई गाँवों का संपर्क टूट गया।

एक अधिकारी ने बताया कि नदी के उफान पर आने से कोटली गाँव के कई घर पानी में डूब गए, जबकि हमीरपुर में पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिससे सड़क संपर्क टूट गया और गाँव पूरी तरह से कट गया।

जम्मू (ग्रामीण) पुलिस ने एक सार्वजनिक परामर्श जारी कर लोगों से नदी के किनारों से दूर रहने और बच्चों को घर के अंदर ही रहने का आग्रह किया है।

अधिकारी ने बताया, ''गरखल ग्राम पंचायत में गुज्जर समुदाय के लगभग 40 सदस्यों के फंसे होने के बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। प्रशासन ने उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के लिए एक बड़ा बचाव अभियान शुरू किया है।'' उन्होंने आगे बताया कि स्थिति पर नजर रखने के लिए टीमें जमीन पर मौजूद हैं। एक अधिकारी ने

बताया कि चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद अखनूर में पुराने पुल को बंद कर दिया गया है और प्रशासन ने यात्रियों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने का आग्रह किया है।

जम्मू–कश्मीर में मंगलवार से जारी भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार सुबह 8:30 बजे से बुधवार सुबह 5:30 बजे तक रियासी में 203 मिमी, कटरा में 193 मिमी, बटोटे में 157.3 मिमी, डोडा में 114 मिमी और भद्रवाह में 96.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। जम्मू वेधशाला ने इसी अवधि में 81 मिमी बारिश दर्ज की।

अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले परिवारों को जल स्तर कम होने तक अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

लगातार बारिश के कारण आज जोजिला दर्रे पर बजरी नाले में फिर से भूस्खलन हुआ, जिससे महत्वपूर्ण श्रीनगर–लेह राजमार्ग बंद हो गया और कश्मीर और लद्दाख के बीच यातायात बाधित हो गया।

अधिकारियों ने बताया कि मलबा हटाने के लिए कर्मचारियों और मशीनों को लगाया गया है, लेकिन भारी बारिश के कारण पुनर्निर्माण कार्य में बाधा आ रही है।

उन्होंने कहा, ''मलबा हटाने का काम पूरा होने तक राजमार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा।''

वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जम्मू–कश्मीर के रियासी में बारिश से प्रभावित 1,000 परिवारों की मदद की

इसके अलावा, पुराना दारूर गांव के परिवार जिनके घर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें इस चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन के अनुरोध पर अस्थायी रूप से श्राइन बोर्ड के निहारिका कॉम्प्लेक्स के शक्ति भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है, श्राइन बोर्ड ने एक बयान में कहा। शुरुआत में, कटरा और आसपास के इलाकों में प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए 400 परिवारों के लिए राहत आपूर्ति रियासी जिला प्रशासन को सौंप दी गई थी। बयान में कहा गया है कि राहत सामग्री में तत्काल जरूरतों को पूरा करने और आपदा के बाद से निपटने में मदद करने के लिए सूखा राशन किट, बर्तन, कंबल, दवाइयां, बाल्टी, तिरपाल और टेंट शामिल हैं। एसएमवीडीएसबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन कुमार वैश्य ने स्थानीय समुदाय को, विशेष रूप से संकट के समय, सहायता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और इस बात पर जोर दिया कि रियासी जिला प्रशासन के साथ समन्वय में, श्राइन बोर्ड प्रभावित परिवारों की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें व्यापक सहायता प्रदान करेगा। बयान में कहा गया है कि श्राइन बोर्ड ने पहले भी संकट के समय, जिसमें कोविड–19 महामारी और अन्य आपदाएँ भी शामिल हैं, समुदाय की सेवा के लिए ऐसी पहल की है। (एजेंसियाँ)

हिमाचल में भारी बारिशः भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 7 हुई, सड़कें और स्कूल बंद

खराब मौसम को देखते हुए, एक आदेश में कहा गया है कि राज्य में सभी सरकारी और निजी कॉलेज और स्कूल 7 सितंबर तक बंद रहेंगे।

अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार शाम सुंदरनगर इलाके में बीबीएमबी कॉलोनी के पास हुए भूस्खलन में मारे गए लोगों में से चार और शव बरामद किए गए हैं, जिससे मृतकों की संख्या सात हो गई है।

सुंदरनगर के उप–मंडल मजिस्ट्रेट अमर नेगी ने बताया कि सात मृतकों में से पाँच एक ही परिवार के सदस्य थे।

एसडीएम ने बताया कि मृतकों में से तीन की पहचान सुरिंदर कौर, उनके बेटे गुरप्रीत सिंह और प्रकाश शर्मा के रूप में हुई है, जबकि अन्य के विवरण का इंतजार है।

अधिकारियों ने बताया कि कुल्लू जिले के अखाड़ा बाजार इलाके में मंगलवार देर रात भूस्खलन के बाद दो मकान ढह जाने से एक एनडीआरएफ जवान समेत दो लोगों के मारे जाने की आशंका है।

मृतकों की पहचान एनडीआरएफ जवान नरिंदर (37) और एक कश्मीरी युवक वकार अहमद (24) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि बचाव अभियान जारी है।

किन्नौर जिले के वांगटू में सड़क किनारे खड़े पांच ट्रक पहाड़ी से गिरे पत्थरों के कारण क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे और अधिक तबाही की खबरें आती रहीं, जबकि मंडी के जोगिंदरनगर के कुंदुनी गांव में भूस्खलन के खतरे के बाद 15 घरों के निवासियों को निकाला गया।

अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार रात सोलन जिले के कंडाघाट के चौहरा गांव में एक घर पर पहाड़ का मलबा गिरने से निवासी बाल–बाल बच गए। अधिकारियों ने

बताया कि पिछले चार दिनों में भारी बारिश के बाद बिलासपुर जिले के जामली इलाके में एक प्राथमिक विद्यालय की पिछली दीवार ढह गई और पानी इमारत में घुस गया।

शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने कहा कि शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों को भी कॉलेजों और स्कूलों में जाने से छूट दी जाएगी। हालांकि, संस्थानों के प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि जब भी संभव हो, कक्षाएं ऑनलाइन मोड के माध्यम से संचालित की जाएं।

आदेश में कहा गया है कि मौजूदा खराब मौसम के कारण पूरे राज्य में कई जगहों पर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होने की प्रबल संभावना है और इसलिए छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। आदेश में आगे कहा

गया है कि शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों को इस अवधि के दौरान बुनियादी ढांचे और चल संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और चल संपत्तियों और स्कूल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए सतर्क रहना चाहिए।

राज्य में 1,162 सड़कें अवरुद्ध होने से सड़क यात्रा बाधित हुई। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (एसईओसी) के अनुसार, मंडी में 289, शिमला में 234, कुल्लू में 205 और सिरमौर जिले में 137 सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि चंबा जिले से विवरण की प्रतीक्षा है।

केंद्र ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग–3 (मंडी–धर्मपुर मार्ग), राष्ट्रीय राजमार्ग–5 (पुराना हिंदुस्तान–तिब्बत मार्ग), राष्ट्रीय राजमार्ग–21 (चंडीगढ़–मनाली मार्ग), राष्ट्रीय राजमार्ग–205 (खरड़ से स्वारघाट), राष्ट्रीय राजमार्ग 305 (औट–सैंज मार्ग), राष्ट्रीय राजमार्ग–505 खाब से ग्राम्फू और राष्ट्रीय राजमार्ग 707 (हाटकोटी से पांवटा) अवरुद्ध हैं।

शिमला–कालका मार्ग पर भूस्खलन के कारण इस मार्ग पर चलने वाली ट्रेनें शुक्रवार (5 सितंबर) तक रद्द कर दी गई हैं।

हिमाचल के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश जारी रही, जहां मंगलवार रात से नैना देवी में 136 मिमी, जोत में 100.6 मिमी, पच्छाद में 77 मिमी, कोठी में 68.4 मिमी, चंबा में 66 मिमी, बिलासपुर में 60.4 मिमी, रोहड़ू में 60 मिमी, मनाली में 57 मिमी, पालमपुर में 52.6 मिमी, कसौली में 49.5 मिमी, कंडाघाट और ददाहू में 48–48 मिमी, सराहन में 44.5 मिमी, सोलन में 43.6 मिमी, काहू में 43.5 और मलरांव में 40 मिमी बारिश हुई।

स्थानीय मौसम विभाग ने बुधवार को राज्य के अलग–अलग इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की नारंगी चेतावनी जारी की है। 20 जून को हिमाचल में मानसून के आगमन के बाद से, राज्य में 95 बार अचानक बाढ़, 45 बार बादल फटने और 122 बड़े भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं।

मानसून शुरू होने के बाद से बारिश से जुड़ी घटनाओं और सड़क हादसों में कम से कम 341 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 41 लोग लापता हैं।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस मानसून में अब तक राज्य को 3,525 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। (एजेंसियाँ)

जम्मू में उच्च जोखिम वाले बचाव अभियान में बीएसएफ के हेलीकॉप्टरों ने 45 फंसे ग्रामीणों को बचाया

करने के बाद, नागरिक प्रशासन ने कीमती जान बचाने के लिए बीएसएफ से एक हेलीकॉप्टर मँगवाया।

अधिकारियों ने बताया कि बीएसएफ ने इस कॉल पर तुरंत कार्रवाई की और उसके हेलीकॉप्टर ने लगातार बारिश के बावजूद तीन उड़ानें भरकर फंसे हुए गांव से 45 नागरिकों को सफलतापूर्वक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।

उपराज्यपाल ने स्थिति का जायजा लिया, राजौरी में हुई त्रासदी पर शोक व्यक्त किया

के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया और पुलवामा तथा शोपियाँ में खानाबदोश परिवारों को जिला प्रशासन द्वारा आश्रय प्रदान किया गया।

श्रीनगर शहर में, आपातकालीन स्थिति के लिए लगभग 9 राहत शिविर तैयार हैं। उपराज्यपाल ने वरिष्ठ अधिकारियों से जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए सभी आवश्यक उपाय करने को कहा। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से प्रभावित परिवारों को राशन, कंबल, दवाइयाँ, रसोई गैस और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने और बिजली के बुनियादी ढाँचे की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने लोगों से हर संभव सावधानी और सुरक्षा उपाय करने का आग्रह किया। उपराज्यपाल ने यह भी आश्वासन दिया कि केंद्र जरूरतमंद लोगों को समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।

उन्होंने राजौरी जिले के कांगड़ी, सुंदरबनी में हुई त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है तथा लगातार बारिश से प्रभावित सभी लोगों की कुशलता की कामना की है।

कश्मीर विश्वविद्यालय और क्लस्टर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित

देखते हुए, क्लस्टर विश्वविद्यालय श्रीनगर की 04–09–2025 को होने वाली सभी परीक्षाएँ स्थगित की जाती हैं। स्थगित परीक्षाओं की नई तिथियाँ अलग से अधिसूचित की जाएँगी।''

जम्मू–कश्मीर को 190 अतिरिक्त एमबीबीएस सीटें मिली

हैं। इस विकास के साथ, जम्मू–कश्मीर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल संख्या अब 1,185 से बढ़कर 1,375 हो गई है।

यह समयोचित वृद्धि जम्मू–कश्मीर के इच्छुक मेडिकल छात्रों के लिए अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी, प्रतिस्पर्धा का दबाव कम करेगी और अधिक प्रशिक्षित डॉक्टरों के उत्पादन द्वारा स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली को दीर्घकालिक रूप से सु.ढ़ बनाने में योगदान देगी। अधिकारियों ने आगे संकेत दिया है कि तीसरे दौर की काउंसलिंग से पहले और सीटों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा की क्षमता का और विस्तार होगा।

जम्मू–कश्मीर के मुख्य सचिव ने इस उपलब्धि को प्राप्त करने में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के निरंतर प्रयासों की सराहना की है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रति आभार व्यक्त किया है। सीट वृद्धि में मार्गदर्शन और सहयोग के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. पॉल का भी आभार व्यक्त किया है।

यह उल्लेख करना उचित है कि डॉ. वीके पॉल स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग जम्मू–कश्मीर से जुड़े हुए हैं और स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में कई पहलों और सुधारों पर काम कर रहे हैं, जिनसे जम्मू–कश्मीर के स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तनकारी बदलाव आने की उम्मीद है।

बीडीओ समेत तीन अधिकारियों को अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए कारण बताओ नोटिस जारी

स्वी.त नहीं की जाएगी।

रियासी के अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त सुखदेव सिंह सम्याल ने चसाना, माहौर, गुलाबगढ़ के खंड विकास अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, माहौर के एक सहायक कार्यकारी अभियंता और विभाग के एक वरिष्ठ सहायक को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

"आपको इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से दो दिनों के भीतर सहायक आयुक्त विकास, रियासी, एसडीएम माहौर के माध्यम से मुख्यालय से आपकी अनधि.त अनुपस्थिति के कारणों को स्पष्ट करते हुए एक लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।

आदेश में कहा गया है, "आपको यह भी कारण बताने की आवश्यकता है कि इस चूक के लिए आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।" इसमें कहा गया है कि रियासी के डिप्टी कमिश्नर ने 29 अगस्त को सामान्य प्रशासन विभाग के कर्मचारियों को बिना मंजूरी के मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश को दोहराया। हालांकि, अधिकारियों ने माहौर के उप–विभागीय मजिस्ट्रेट या किसी सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना अपना मुख्यालय छोड़ दिया था, जो निर्देशों का उल्लंघन है, नोटिस में कहा गया है। अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त ने कहा कि पूरा जिला भूस्खलन और बादल फटने के गंभीर खतरे में है, लगातार बारिश के कारण गुलाबगढ़ से पहले ही सात मौतें हो चुकी हैं।

डॉ. जितेंद्र ने केंद्रीय सचिवों की संयुक्त बैठक बुलाई, स्टार्टअप्स को सहयोग देने पर जोर दिया

नई दिल्ली, 3 सितंबरः केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां नवनिर्मित कर्तव्य भवन में सभी विज्ञान सचिवों की एक उच्चस्तरीय आवधिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। नॉर्थ ब्लॉक से मंत्रालय के स्थानांतरण के बाद नए परिसर में यह पहली ऐसी संयुक्त बैठक थी।

बैठक में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय कुमार सूद के साथ–साथ विज्ञान सचिव और परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

आगामी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (आईआईएसएफ) की तैयारियों की समीक्षा करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने सभी विभागों को स्टार्टअप्स का मार्गदर्शन और पोषण करने तथा राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सवों में उनका एकीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। देश के विभिन्न भागों में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला आईआईएसएफ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक जन–केंद्रित मंच के रूप में उभरा है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने आगामी उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन (ईएसटीआईसी) पर भी विस्तृत जानकारी दी। यह भारत का प्रमुख वार्षिक मंच है जो विभिन्न मंत्रालयों, नवप्रवर्तकों, नोबेल पुरस्कार विजेताओं, वैश्विक विशेषज्ञों और युवा नेताओं को एक साथ लाता है।

उन्होंने कहा कि ईएसटीआईसी अत्याधुनिक अनुसंधान, गहन तकनीकी सफलताओं और विचारोत्तेजक चर्चाओं को प्रदर्शित करेगा, जिससे ''विकसित भारत 2047'' की दिशा में वैज्ञानिक नेतृत्व के एक नए युग का सूत्रपात होगा।

समीक्षा के दौरान, डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जेव–ईङ (जैव–अर्थव्यवस्था, रोजगार, पर्यावरण) नीति पर दिए गए जोर को याद किया और सभी विभागों से जैव प्रौद्योगिकी और उससे जुड़े उभरते क्षेत्रों में प्रयास बढ़ाने का आह्वान किया, जिनमें भारतीय अर्थव्यवस्था में मूल्यवर्धन की अपार संभावनाएँ हैं।

मंत्री ने कई क्षेत्रों में भारी बारिश की पृष्ठभूमि में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (डवमै) और भारत मौसम विज्ञान विभाग (प्डव) के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने बेहतर तैयारी और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक समय की सूचना प्रसार और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने के महत्व पर बल दिया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने पिछली मासिक बैठक में दिए गए निर्देशों पर डीएसटी, डीबीटी, सीएसआईआर, इसरो और एमओईएस द्वारा की गई कार्रवाई की व्यापक समीक्षा की। सरकार की ओर से विज्ञान संचार बढ़ाने पर एक विशेष प्रस्तुति भी दी गई, जिसके बाद सभी सचिवों के साथ विचार–मंथन सत्र हुआ।

बैठक में प्रतिभागियों में परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. अजीत कुमार मोहंतीय जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ. राजेश गोखलेय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ. एम. रविचंद्रनय इसरो के अध्यक्ष डॉ. वी. नारायणन (जो वर्चुअली शामिल हुए)य और डॉ. मृत्युंजय महापात्रा, महानिदेशक, आईएमडी, के साथ–साथ डीएसटी, डीबीटी, सीएसआईआर, इसरो, एमओईएस और अन्य विज्ञान विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

बीएसएफ ने भविष्य की लड़ाइयों के लिए सैनिकों को प्रशिक्षित करने हेतु ड्रोन युद्ध स्कूल शुरू किया

नई दिल्ली, 3 सितंबरः पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाला बीएसएफ, रिमोट–नियंत्रित हवाई प्लेटफार्मों से जुड़े आधुनिक युद्ध के लिए ''ड्रोन कमांडो'' और ''ड्रोन योद्धाओं'' की विशेष इकाइयों को प्रशिक्षित कर रहा है, और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशनों में तैनात करने की योजना है।

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के टेकनपुर स्थित बल के अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में 'ड्रोन युद्ध स्कूल' का उद्घाटन किया।

पीटीआई ने जुलाई में खबर दी थी कि करीब 2.65 लाख कर्मियों वाला बल ऑपरेशन सिंदूर से सीखे गए सबक के बाद अपना पहला "ड्रोन स्क्वाड्रन" तैयार कर रहा है।

बल के प्रवक्ता ने कहा, ''ड्रोन युद्ध स्कूल, बल के सीमा रक्षक सैनिकों को आधुनिक सामरिक चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करेगा।''

उन्होंने कहा, ''संस्थान पांच विशेष पाठ्यक्रमों के माध्यम से ड्रोन कमांडो और ड्रोन योद्धाओं को तैयार करेगा, जिसमें मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) संचालन, ड्रोन विरोधी युद्ध और निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्र करना शामिल है।''

स्कूल में सिमुलेटर और लाइव ड्रोन उड़ान क्षेत्र, यूएवी और रात्रि संचालन में पेलोड एकीकरण के लिए सुविधाएं, रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ) जैमर और काइनेटिक इंटरसेप्टर के लिए उपकरण, इसके अलावा लिंक्ड हार्डवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) उपकरण भी मौजूद हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्कूल के उद्घाटन के बाद बीएसएफ महानिदेशक ने प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया और तीन साल से चल रहे रूस–यूक्रेन युद्ध के बारे में बात की, जिसमें ड्रोन ने कुछ अन्य लड़ाइयों के अलावा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर से प्राप्त रणनीतिक सीख के बारे में भी बताया।

अधिकारी ने बताया कि चौधरी ने युद्ध में एआई और मशीन लर्निंग (एमएल) की भूमिका, निर्णायक परिणामों के लिए सक्रिय और हथियारबंद ड्रोन के उपयोग, एफपीवी (कामिकेज ड्रोन के रिमोट पायलटिंग से संबंधित प्रथम व्यक्ति .श्य) के महत्व और राष्ट्रीय नीतियों में रणनीतिक बदलावों के बारे में भी बात की।

अगस्त में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ''अद्वितीय वीरता'' और ''अद्वितीय वीरता'' का प्रदर्शन करने के लिए बीएसएफ के अठारह जवानों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया। इनमें दो ऐसे जवान भी शामिल थे जिन्हें मरणोपरांत सेना द्वारा प्रदान किया गया वीर चक्र प्रदान किया गया।

यह बल चीन निर्मित पाकिस्तानी ड्रोनों से भी निपटता है जो प्रतिदिन देश के पश्चिमी भाग में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से भारत में ड्रग्स, हथियार और गोला–बारूद की तस्करी करते हैं।

बीएसएफ को सेना की परिचालन कमान के तहत नियंत्रण रेखा (एलओसी) के अलावा 2,290 किलोमीटर लंबी भारत–पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) और पूर्वी तरफ बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा का काम सौंपा गया है। (पीटीआई)

रफ़्तार समाचार, स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक अर्जुन सिंह द्वारा शंकर प्रिंटर्स रेहड़ी कालोनी जम्मू (जम्मू व कश्मीर) से प्रकाशित तथा जम्मू से मुद्रित। संपादक – अर्जुन सिंह मो. 9419156797 कार्यालय फोन न. 01991–245797 Email: raftarsamachar@gmail.com आरएनआई न. JKHIN/2011/38527 पीआरसी एक्ट के तहत सभी समाचारों व सामग्री के चयन तथा संपादन के लिए उत्तरदायी किसी भी विवाद का निपटारा जिला रियासी व जम्मू व कश्मीर में ही होगा।

कश्मीर में सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल कल बंद रहेंगे: डिव कॉम कश्मीर

श्रीनगर, 3 सितंबरः अधिकारियों ने बुधवार को घाटी भर के शैक्षणिक संस्थानों को कल बंद रखने की घोषणा की।

कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने केएनसी को बताया कि प्रतिकूल मौसम को देखते हुए 4 सितंबर, 2025 को सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल बंद रहेंगे।

उन्होंने कहा कि यह कदम पूरी तरह से छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर उठाया गया है।

जम्मू–कटरा रेल सेवाएं बाढ़ से प्रभावित, शटल परिचालन रद्द

जम्मू, 3 सितंबरः स्थानीय लोगों और फंसे हुए यात्रियों की मदद के लिए माता वैष्णो देवी मंदिर के आधार शिविर जम्मू और कटरा के बीच यात्रा करने के लिए शुरू की गई चार ट्रेनों की शटल सेवाएं बुधवार को भारी बारिश और बाढ़ के कारण निलंबित कर दी गईं।

नई दिल्ली से कटरा के लिए निर्धारित ट्रेन सेवाओं को भी जल्द ही समाप्त कर दिया गया है।

1 सितंबर से शुरू हुई ये शटल सेवाएं 15 सितंबर तक चलने वाली थीं।

रेलवे के एक अधिकारी ने कहा, ''जम्मू और कटरा के बीच शटल सेवाएं, जो दैनिक यात्रियों और फंसे हुए लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू की गई थीं, आज रद्द कर दी गई हैं।''

उन्होंने कहा कि भारी बारिश और ट्रैक पर बाढ़ को देखते हुए यह कदम उठाया गया।

पठानकोट–जम्मू खंड में 26 अगस्त को भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के कारण हुई गड़बड़ी और दरारों के कारण जम्मू रेलवे डिवीजन में रेल यातायात पिछले नौ दिनों से निलंबित है। हालांकि, रेलवे फंसे हुए यात्रियों को जम्मू से उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनें चला रहा है।

पिछले चार दिनों में, कुल 5,784 फंसे हुए यात्रियों को सात विशेष ट्रेनों में ले जाया गया है।

26 अगस्त से लगातार हो रही बारिश के कारण इस क्षेत्र में रेल और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिससे कई तीर्थयात्री फँस गए हैं। 26 अगस्त को कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर के पास हुए भूस्खलन में 34 लोगों की मौत हो गई थी। बुधवार को नौवें दिन भी तीर्थयात्रा स्थगित रही।

पिछले बुधवार को जम्मू में 1910 के बाद से सबसे ज़्यादा 380 मिमी बारिश दर्ज की गई। (एजेंसियाँ)

सकीना इटू ने सभी डॉक्टरों, पैरामेडिक्स से उपलब्ध रहने की अपील की

श्रीनगर, 3 सितंबरः स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने सभी डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों से अपील की है कि वे खराब मौसम को देखते हुए आम जनता की भलाई के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध रहें।

यहाँ जारी एक संदेश में, मंत्री ने कहा, ''खराब मौसम को देखते हुए, मैं सभी डॉक्टरों, पैरामेडिक्स, अस्पताल कर्मचारियों और प्रशासन से चौबीसों घंटे उपलब्ध रहने की अपील करती हूँ। लगातार बारिश एक गंभीर खतरा पैदा करती है और हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य अपने लोगों के प्रति है। आइए हम निस्वार्थ भाव से सेवा करें, एकजुट रहें और एक–दूसरे का समर्थन करें। मोहल्ला और मस्जिद कमेटियों को समुदायों का मार्गदर्शन करना चाहिए, जबकि पुलिस और प्रशासन सहायता के लिए मौजूद हैं। अल्लाह की रहमत से, हम इस कठिन समय से उबर जाएँगे।''

भारी बारिश के कारण जम्मू संभाग में स्कूल 5 सितंबर तक बंद रहेंगे

जम्मू, 3 सितंबरः लगातार भारी बारिश और आईएमडी द्वारा जारी मौसम संबंधी चेतावनी के मद्देनजर, जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूल 5 सितंबर, 2025 तक बंद रहेंगे।

स्कूल शिक्षा निदेशालय, जम्मू द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है क्योंकि कई क्षेत्रों में भूस्खलन, अचानक बाढ़ और गंभीर जलभराव का खतरा है। आदेश में आगे कहा गया है कि शिक्षा की निरंतरता बनाए रखने के लिए जहाँ भी संभव हो, ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जानी चाहिए।

चौथे पुल के पास बाढ़ को रोकने के लिए बहु–एजेंसी अभियान जारी

जम्मू, 3 सितंबरः जम्मू शहर में उफनती तवी नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते अधिकारियों ने निचले इलाकों में बाढ़ को रोकने के लिए क्षतिग्रस्त चौथे पुल के पास तटबंधों को मजबूत करने के लिए कई एजेंसियों के साथ मिलकर अभियान शुरू किया है।

जम्मू में भारी बारिश के कारण 26 अगस्त को चौथे तवी पुल के पास सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे टूटे हुए हिस्से पर कई वाहन फंस गए थे।

पुलिस अधीक्षक अजय शर्मा ने संवाददाताओं को बताया, ''अगर इस इलाके में कोई दरार आती है, तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। नागरिक प्रशासन, पुलिस और सेना इसे रोकने के लिए अभियान चला रहे हैं। इंजीनियरिंग विंग इस पर काम कर रही है।''

वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं।

चौथे पुल के पास का इलाका निचले इलाकों में होने के कारण दरार के कारण बड़े इलाके जलमग्न हो सकते हैं। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और इन संवेदनशील इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है।

एसपी ने कहा, ''अगर कोई दरार आती है, तो यहाँ भीषण बाढ़ आने की संभावना है। मैंने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने का प्रयास करने को कहा है। सबसे पहले महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाना चाहिए।''

उन्होंने कहा कि हालाँकि, तत्काल कोई खतरा नहीं है क्योंकि इलाके की सुरक्षा के लिए अभियान जारी है। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण पानी के और रिसाव को रोकने के लिए सेना के जवानों और इंजीनियरिंग टीमों ने दरार के एक बड़े हिस्से पर बड़े वाटरप्रूफ कवर लगा दिए हैं।

क्षतिग्रस्त सड़क के चारों ओर कंटीले तारों से इलाके को सील कर दिया गया है।

शहर के चौथे पुल को जोड़ने वाली सड़क के एक हिस्से के बह जाने से हुई ''दरार'' से एक निचली बस्ती सिर्फ 49 से 50 मीटर की दूरी पर है।

पड़ोसी इलाकों के चिंतित निवासियों की रातों की नींद उड़ी हुई है। इस क्षेत्र की आबादी लगभग 7,000 है और यहाँ एक बड़ा व्यापारिक केंद्र, नेहरू वेयरहाउस स्थित है।

रियासी पुलिस की बड़ी कामयाबी, फरार आरोपियों को किया गिरफ्तार

रफ्तार समाचार ब्यूरो
रियासी 03 सितंबर। लगातार खराब मौसम और दुर्गम इलाकों के बावजूद रियासी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए थाना चसाना में दर्ज एफआईआर संख्या 42ध्2025 के दो फरार आरोपियों को गिरतार कर लिया है। गिरतार किए गए आरोपियों की पहचान शबीर अहमद और जाकिर हुसैन, पुत्र रोशन दीन, निवासी कोटली चन्ना, तहसील चसाना, जिला रियासी के रूप में हुई है।

दोनों आरोपी लंबे समय से गिरतारी से बचने के लिए लगातार मौसम और इलाके की कठिन परिस्थितियों का सहारा ले रहे थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी रियासी परमवीर सिंह, जेकेपीएस ने विशेष टीम का गठन किया, जिसमें थाना प्रभारी चसाना को एसडीपीओ महौर विकार यूनुस, जेकेपीएस की देखरेख में लगाया गया। पुलिस टीम ने तकनीकी सहायता और पुख्ता सुरागों के आधार पर तलाशी अभियान चलाया और कठिन हालात में भी दबिश दी। भारी बारिश, भूस्खलन, बिजली कटौती और सड़कों पर रुकावट जैसी चुनौतियों के बावजूद पुलिस टीम ने हिम्मत और पेशेवराना तरीके से आरोपियों को गिरतार कर लिया। दोनों आरोपी स्थानीय महिलाओं पर डंडों और मुक्कों से हमला करने के मामले में शामिल थे, जिसमें गंभीर चोटें आई थीं। रियासी पुलिस ने साफ किया है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और चाहे मौसम हो या पहाड़ी इलाका, पुलिस अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेगी।

रियासी में बड़ी कार्रवाई : 13 अधिकारियों को ड्यूटी से गायब रहने पर कारण बताओ नोटिस

रफ्तार समाचार ब्यूरो
रियासी 03 सितंबर। लगातार खराब मौसम और राहत कार्यों के बीच रियासी जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए 13 अधिकारियों व कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

जिला विकास आयुक्त रियासी निधि मलिक के निर्देश पर यह कदम उठाया गया। प्रशासन ने पहले ही सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियाँ रद्द कर दी थीं और आदेश दिया था कि कोई भी अधिकारी बिना अनुमति अपने स्टेशन से अनुपस्थित नहीं रहेगा। इसके बावजूद 13 अधिकारी और कर्मचारी.जिनमें आठ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (बीडीओ) मुख्य .षि अधिकारी, जिला .षि अधिकारी, धर्ममाड़ी का एक मेडिकल ऑफिसर, एक सहायक कार्यकारी अभियंता (एईई) और माहौर उपमंडल का एक वरिष्ठ सहायक शामिल हैं.बिना अनुमति ड्यूटी से नदारद पाए गए।

प्रशासन ने इस गैर–जिम्मेदाराना रवैये को गंभीर लापरवाही और सरकारी आदेशों की खुली अवहेलना बताया है। सभी से स्पष्टीकरण माँगा गया है और साफ चेतावनी दी गई है कि राहत व बहाली कार्यों के बीच आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने दोहराया है कि मौजूदा हालात में हर अधिकारी व कर्मचारी की मौजूदगी अनिवार्य है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कटरा वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन का खतरा, प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया

रफ्तार समाचार ब्यूरो
कटरा 03 सितंबर। लगातार हो रही बारिश से श्री माता वैष्णो देवी मार्ग पर पुराने दरूड़ डावे मोड़ स्थित दुकानें, घोड़ों के शेड और मकान भूस्खलन की जद में आ गए हैं। जमीन खिसकने के खतरे को देखते हुए स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से सुरक्षित आश्रय की मांग की थी।

युवा नेता सोहन चंद और समाज सेवक सोनू ठाकुर के प्रयासों से श्राइन बोर्ड प्रशासन ने तुरंत कदम उठाते हुए प्रभावित परिवारों को अपने वाहनों के माध्यम से निहारिका भवन स्थित आशीर्वाद भवन में शिट किया।

स्थानीय लोगों ने राहत और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन एवं सहयोगी संस्थाओं का आभार जताया है।

रियासी जिला अस्पताल मुख्य गेट के बाहर नाले के पानी से सड़क का कटाव, फल की रेहड़ी गिरी

रफ्तार समाचार ब्यूरो
कटरा 03 सितंबर। लगातार बारिश के चलते रियासी जिला अस्पताल के मुख्य गेट के बाहर सड़क का एक हिस्सा नाले के तेज बहाव में कट गया। इस दौरान वहां खड़ी फल की एक रेहड़ी भी सामान सहित नाले में जा गिरी। गनीमत यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नाले के पानी का तेज बहाव सड़क के किनारे लगातार कटाव कर रहा है, जिससे आसपास की जगह भी खतरे की जद में आ गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द पक्की दीवार व सुरक्षा उपाय किए जाएं, ताकि बड़े हादसे को टाला जा सके।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार स्थिति पर नजर रखी जा रही है और संबंधित विभाग को अलर्ट किया गया है।

सलाल में जमीन खिसकी

रफ्तार समाचार ब्यूरो
रियासी 03 सितंबर। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सलाल (ससुंडा) क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जमीन खिसकने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार यहां लगभग 100 मीटर से ज्यादा क्षेत्र खिसक चुका है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश का पानी लगातार ढलानों में रिसने से मिट्टी और चट्टानें खिसक रही हैं, जिससे सड़क और आसपास के घरों को भी खतरा पैदा हो गया है। हालात यह हैं कि लोग अपने घरों को सुरक्षित करने की कोशिश में लगे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि जितना भी सलाल कोटली पंचायत नुकघ्सान हुआ है प्रशासन को इस घटना की जानकारी दे दी गई है और मौके पर हालात का जायजा लेने सलाल के मुख्या लोग पहुंचे। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित इलाके में तुरंत सुरक्षा इंतजाम किए जाएं ताकि किसी भी तरह की जान–माल की हानि से बचा जा सके।

बनिहाल रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में प्रसव के बाद रेलवे कर्मचारियों ने महिला और नवजात शिशु को अस्पताल पहुँचाया'

रोहित शर्मा
जम्मू, सितंबर 3। जम्मू मंडल में कश्मीर घाटी के बनिहाल रेलवे स्टेशन के रेलवे कर्मचारियों ने बनिहाल स्टेशन के पास ट्रेन में प्रसव के बाद एक महिला यात्री और उसके नवजात शिशु को स्थानीय अस्पताल पहुँचाया। अख्तरा बानो नाम की महिला यात्री यात्रा के दौरान अपने पति श्री मोहम्मद अशरफ के साथ थीं और वे सुंबर गाँव के निवासी थे। परिवार ट्रेन संख्या 64651 में यात्रा कर रहा था, जो एक अनारक्षित ट्रेन है और कश्मीर में संगलदान और बारामूला के बीच प्रतिदिन चलती है।

जैसे ही ट्रेन बनिहाल पहुँची, महिला को तेज प्रसव पीड़ा होने लगी। उसने महिला सह–यात्रियों की मदद से ट्रेन में ही एक बच्चे को जन्म दिया। ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने तुरंत स्टेशन मास्टर को सूचित किया। सूचना मिलते ही बनिहाल स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक श्री एबी बाली और अन्य रेलवे कर्मचारी श्री ललित कुमार, मुदस्सिर अहमद, मंजूर अहमद ने बच्चे को आगे के इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की। ताकि मां और बच्चे को आवश्यक उपचार मिल सके। इस दौरान ट्रेन और स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी स्टाफ भी मौजूद था। परिवार ने रेलवे कर्मचारियों को उनकी त्वरित प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद दिया। इस घटना पर, जम्मू मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक श्री उचित सिंघल तथा कश्मीर घाटी के रेलवे एरिया मैनेजर श्री साकिब युसूफ ने मुश्किल समय में मदद करने वाले यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों की तत्परता और मानवता की प्रशंसा की। और कहा कि यह घटना कर्मचारी और आम यात्रियों के बीच समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसने एक जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारी भूस्खलन से ज्योतिपुरम, सलाल सड़क बंद

रफ्तार समाचार ब्यूरो
रियासी 03 सितंबर। लगातार हो रही बारिश के कारण ज्योतिपुरम.सलाल सड़क पर चौक पोस्ट के पास सलाल वाली साइड भारी भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन की वजह से सड़क पूरी तरह बंद हो गई है, जिससे आम जनता और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर चट्टानें और मलबा गिरने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। वहीं प्रशासन और संबंधित विभाग की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और सड़क को जल्द बहाल करने के लिए राहत व मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे खराब मौसम और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए फिलहाल इस मार्ग का इस्तेमाल न करें और सुरक्षित रास्तों का ही चयन करें।

रियासी आपदा पर विधायक कुलदीप राज दुबे का बड़ा ऐलान, 1 करोड़ रुपये तुरंत जारी हों राहत के लिए

रफ्तार समाचार ब्यूरो
रियासी, 3 सितंबर। लगातार बारिश और प्रा.तिक आपदा से जूझ रहे रियासी जिले के लिए बड़ी खबर सामने आई है। रियासी.57 विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुलदीप राज दुबे ने जिला प्रशासन से कंस्टीट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड (सीडीएफ) से 1 करोड़ रुपये तुरंत जारी करने की मांग की है। विधायक डब्बी ने साफ कहा कि यह राशि सिर्फ और सिर्फ आपदा राहत, आवश्यक सेवाओं की बहाली और प्रभावित परिवारों की मदद में इस्तेमाल की जाए। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि पीड़ित जनता की उम्मीदों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

दुबे ने जोर देकर कहा . "राहत कार्यों में देरी और लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगी, हर एक रुपये का उपयोग पारदर्शी और समयबद्ध होना चाहिए। रियासी की जनता अब राहत की उम्मीद लगाए बैठी है और देखना यह होगा कि प्रशासन कितनी तेजी से इस 1 करोड़ की राशि को जमीन पर उतारता है।

महौर में बारिश का तांडव 86 से अधिक घर तबाह, 90 परिवारों को रातों–रात सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया

रफ्तार समाचार ब्यूरो

रियासी, 3 सितंबर। महौर उपमंडल में आसमान से बरस रही आफत ने लोगों की नींद उड़ा दी है। लगातार हो रही मूसलधार बारिश से इलाके में भारी तबाही मच गई है। अब तक 86 से अधिक मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जबकि हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने 90 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया।

एसडीएम महौर शफकत मजीद भट ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रशासन की टीमें दिन–रात राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। राहत की बात यह है कि अब तक किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं मिली है। भारी बारिश से जगह–जगह भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ (लैश लड) ने सड़क तंत्र को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। कई गाँवों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। इसके बावजूद प्रशासन ने खाद्य सामग्री, दवाइयाँ और जरूरी सामान प्रभावित इलाकों तक पहुँचाने की व्यवस्था की है।

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घरों से बाहर निकलते वक्त सतर्क रहें और राहत कार्यों में सहयोग करें।

अघार–बल्लियां के ऊपर पहाड़ी का हिस्सा टूटा, दोनों गांवों पर मंडराया खतरा

रफ्तार समाचार ब्यूरो

रियासी, 3 सितंबर। लगातार हो रही बारिश के कारण मरी ए से अघार बल्लियां नाले के ऊपर वाली पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया है। पहाड़ी खिसकने से नाले के बहाव में और इर्द–गिर्द की जमीन पर खतरा बढ़ गया है।

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अगर बारिश इसी तरह जारी रही तो नाले का पानी रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर सकता है, जिससे दोनों गांवों को भारी नुकसान हो सकता है। फिलहाल लोग दहशत में हैं और कई परिवार एहतियातन सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं।

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि तुरंत प्रभाव से राहत व बचाव कार्य शुरू किए जाएं और प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर आवश्यक कदम उठाए जाएं।

झेलम नदी खतरे के निशान को पार कर गई, कश्मीर में बाढ़ की चेतावनी जारी

श्रीनगर, 3 सितंबरः जम्मू–कश्मीर में अधिकारियों ने बुधवार को बाढ़ की चेतावनी जारी की, क्योंकि अनंतनाग और पंपोर के संगम पर झेलम नदी खतरे के निशान को पार कर गई। दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद कम से कम दो लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लोग फंसे हुए हैं और प्रमुख राजमार्ग बंद हो गए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि संगम में जलस्तर 25 फीट के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर गया है, जबकि पंपोर में नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे कई निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। श्रीनगर शहर में, राम मुंशीबाग में नदी का जलस्तर 18 फीट के चेतावनी निशान के करीब पहुँच गया है।

जम्मू में मंगलवार शाम से हो रही बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं, प्रशासन ने बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है और लोगों को किसी भी जलाशय के पास न जाने की सलाह दी है।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अनुसार, क्षेत्र में जल स्तर बढ़ रहा है और अगर बारिश जारी रही तो और भी बढ़ेगा। विभाग ने ग पर एक पोस्ट में कहा, ''सभी संबंधित अधिकारियों से अनुरोध है कि वे सतर्क रहें और आवश्यक कदम उठाएँ... बाढ़ से संबंधित ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारी तुरंत अपने पदों पर पहुँचें।''

पुलवामा, शोपियां और कुलगाम सहित दक्षिण कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। पुलिस और आपदा प्रबंधन टीमों ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है, जबकि संवेदनशील इलाकों में आपातकालीन हेल्पलाइन सक्रिय कर दी गई हैं।

राजौरी के सुंदरबनी में भारी बारिश के बाद एक घर ढहने से एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई। अखनूर में, चिनाब नदी का जलस्तर निकासी स्तर से चार फीट ऊपर उठने के बाद गरखल गाँव में कम से कम 40 लोग फंस गए हैं। उन्हें निकालने के लिए एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें भेजी गई हैं। एक अन्य घटना में, पक्का डांगा इलाके के काली झानी मोहल्ले में एक पुराना घर ढह गया, जिसके अंदर फंसे तीन लोगों को निकाला गया, पीटीआई ने बताया।

घटना के बाद, बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे स्थानीय विधायक युद्धवीर सेठी ने उपायुक्त को क्षेत्र के सभी पुराने और असुरक्षित मकानों को गिराने का निर्देश दिया।

अनंतनाग पुलिस ने लिद्दर नाले में अचानक वृद्धि के बाद एक पुल के नीचे फंसे 25 खानाबदोश परिवारों को भी बचाया, जबकि कुलगाम में वैशोव नाला के उफान पर आने के बाद ब्राजलू गांव से पांच परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।

कई प्रमुख मार्गों के बंद होने से पूरे क्षेत्र में संपर्क बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उधमपुर और बनिहाल के बीच कई भूस्खलन के कारण सभी मौसम में खुला रहने वाला श्रीनगर–जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार दूसरे दिन बंद रहा। मुगल रोड, जम्मू–श्रीनगर–लेह राजमार्ग और जम्मू–किश्तवाड़ राजमार्ग भी बंद कर दिए गए हैं।

घाटी और जम्मू क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बुधवार को स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए, कश्मीर विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थानों ने अपनी निर्धारित परीक्षाएं स्थगित कर दीं।

कटरा से माता वैष्णो देवी की तीर्थयात्रा लगातार नौवें दिन स्थगित रही

माता वैष्णो देवी मंदिर के ट्रैक पर भूस्खलन, कोई हताहत नहीं

जम्मू, 3 सितंबरः जम्मू–कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी की स्थगित तीर्थयात्रा बुधवार को भूस्खलन की चपेट में आ गई, अधिकारियों ने बताया कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

अधिकारियों ने आगे बताया कि भारी बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर अधिकारियों के आवास भी खाली करा दिए गए हैं।

भूस्खलन ट्रैक के सम्मार पॉइंट पर हुआ, जिससे मंदिर जाने वाला रास्ता अवरुद्ध हो गया। हालाँकि, इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई खबर नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई तीर्थयात्री नहीं था। मलबा हटाने के प्रयास जारी हैं।

बुधवार को नौवें दिन भी तीर्थयात्रा स्थगित रही, जिससे कटरा आधार शिविर श्रद्धालुओं की अनुपस्थिति में वीरान रहा।

अपराधियों को पकड़ने के लिए जेसीबी की बकेट में बैठकर उफनते नाले को पार गई पुलिस

रफ्तार समाचार ब्यूरो

रियासी/चससाना 3 सितंबर। अपराधियों को दबोचने के लिए रियासी पुलिस ने ऐसा कारनामा कर दिखाया, जिसने लोगों के बीच चर्चा छेड़ दी। एसएसओ चसाना रविंदर कुमार के नेतृत्व में पुलिस दल ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए बदौरा नाले का उफान पार किया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार महौर उपमंडल के अंतर्गत आने वाले बदौरा नाले का अस्थायी पुल हाल ही में आई भारी बारिश में बह गया था। इसके चलते नाले को पार करना बेहद जोखिम भरा हो गया था। ऐसे हालात में पुलिस को सूचना मिली कि दो अपराधी नाले के उस पार किसी इलाके में छुपे हुए हैं। पुलिस टीम ने बिना देर किए नाले में काम कर रही जेसीबी मशीनों की मदद ली। पुलिसकर्मी एक जेसीबी की बकेट में बैठकर बीच नाले तक पहुंचे और वहां से दूसरी मशीन की बकेट में शिट होकर आखिरकार उफनते नाले को पार कर गए। इस साहसिक कार्रवाई के बाद पुलिस ने छापामारी कर दोनों अपराधियों को गिरतार कर लिया।

इस घटना ने साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हों, कानून के रखवाले अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। स्थानीय लोग भी पुलिस की इस जांबाजी की सराहना कर रहे हैं।

गृह मंत्रालय ने हवाई अड्डों, बंदरगाहों और रेलवे स्टेशनों पर आव्रजन चौकियों के नाम तय किए

नई दिल्ली, 3 सितंबरः केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के प्रवेश और निकास के लिए 37 हवाई अड्डों, 34 समुद्री और नदी बंदरगाहों और 37 अंतरराष्ट्रीय भूमि पारगमन बिंदुओं को नामित आव्रजन चौकियों के रूप में नामित किया है।

गृह मंत्रालय ने भारत–पाकिस्तान और भारत–बांग्लादेश सीमाओं पर स्थित छह रेलवे स्टेशनों को भी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के प्रवेश और निकास के लिए नामित आव्रजन चौकियों के रूप में नामित किया है।

गृह मंत्रालय ने एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की, जिसके बाद आव्रजन और विदेशी आदेश, 2025 को 1 सितंबर को अधिसूचित किया गया था।

नामित आव्रजन चौकियों वाले हवाई अड्डे अहमदाबाद, लखनऊ, अमृतसर, वाराणसी, बागडोगरा, बैंगलोर, भुवनेश्वर, राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भोपाल, कालीकट (केरल), चंडीगढ़, चेन्नई, कोचीन, कोयंबटूर, डाबोलिम (गोवा), दिल्ली, गया (बिहार), गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर (मध्य प्रदेश), जयपुर, कोलकाता हैं।

अन्य हवाई अड्डे कन्नूर (केरल), मदुरै (तमिलनाडु), मैंगलोर, मुंबई, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मोपा (गोवा), नागपुर, पटना, पोर्ट ब्लेयर, पुणे, श्रीनगर, सूरत, त्रिची (तमिलनाडु), तिरुवनंतपुरम, तिरूपति, विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) हैं।

बंदरगाह हैं अलंग (गुजरात), अगाती और मिनिकॉय द्वीप (लक्षद्वीप), बेदी बंदर (जामनगर, गुजरात), भावनगर (गुजरात), कालीकट (केरल), चेन्नई, कोचीन, कुड्डालोर (चेन्नई), धामरा (ओडिशा), काकीनाडा (आंध्र प्रदेश), कोलकाता, कांडला (गुजरात), कृष्णापट्टनम (आंध्र प्रदेश)।

अन्य बंदरगाह कट्टुपल्ली (तमिलनाडु), करीमगंज (असम), कामराजार (तमिलनाडु), कोल्लम (केरल), मांडवी (गुजरात), मोरमगोआ हार्बर (गोवा), मुंद्रा (गुजरात), मुंबई, न्यू मैंगलोर, नागापट्टिनम (तमिलनाडु), न्हावा शेवा (महाराष्ट्र), पारादीप (ओडिशा), पोरबंदर, पोर्ट ब्लेयर, सिलघाट (असम), तूतीकोरिन (तमिलनाडु), हैं। विशाखापत्तनम, वल्लारपदम, विझिंजम (दोनों केरल), धुबरी, और पांडु (दोनों असम)।

लैंडपोर्ट अटारी रोड, डेरा बाबा नानक (दोनों पंजाब), बनबसा (उत्तराखंड), चांगराबांधा, घोजाडांगा, हरिदासपुर, हिली, जयगांव, लालगोलाघाट, महदीपुर, फुलबारी, राधिकापुर, रानीगंज, गेडे (सभी पश्चिम बंगाल), डालू, डावकी (दोनों मेघालय), दरंगा, करीमगंज, मनकाचर, सुतारकांडी (सभी असम) हैं।

अन्य लैंडपोर्ट हैं अगरतला, धलाईघाट, खोवाल, मुहुरिघाट, रग्ना, कैलाशहर, सबरूम, श्रीमंतपुर (सभी त्रिपुरा), गौरीफंटा, रुपईडीहा, सोनौली (सभी उत्तर प्रदेश), जोगबनी, रक्सौल (दोनों बिहार), मोरेह (मणिपुर), सबरूम (दक्षिण त्रिपुरा), कावरपुइचुआ, जोरिनपुई, जोखावथर (सभी मिजोरम)।

आव्रजन चौकियों वाले रेलवे स्टेशन हैंः मुनाबाव (राजस्थान), अटारी (पंजाब), गेडे रेल और सड़क चेक पोस्ट, पेट्रापोलधचितपुर, हरिदासपुर और न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन (सभी पश्चिम बंगाल)।

(एजेंसियां)

स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के सलाहकार ने सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण कक्ष रामबाग का दौरा किया, बाढ़ की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की

श्रीनगर, 3 सितंबरः स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, समाज कल्याण एवं शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने आज मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी के साथ रामबाग स्थित सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण कक्ष का दौरा किया और बाढ़ की मौजूदा स्थिति और तैयारियों का जायजा लिया। इस

दौरान, मंत्री और सलाहकार ने वर्तमान जल स्तर, मौजूदा निगरानी तंत्र और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों का भी आकलन किया।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण कक्ष में एक संक्षिप्त बैठक की अध्यक्षता करते हुए, सकीना इटू ने अधिकारियों से जनता तक सूचना का वास्तविक समय पर प्रसार करने और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि निचले और बाढ़–प्रवण क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से निकालने के लिए समय पर अलर्ट और सलाह जारी की जाएँ।

मंत्री ने अधिकारियों से झेलम के तटबंधों के पास कर्मचारियों और मशीनरी को सतर्क रखने पर भी जोर दिया ताकि तटबंधों में किसी भी प्रकार की दरार की स्थिति में किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से बचा जा सके।

मंत्री और सलाहकार ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों से आपस में घनिष्ठ तालमेल बनाए रखने और चौबीसों घंटे सतर्कता बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों को सूचित और तैयार रखने के लिए निरंतर जागरूकता उपायों पर जोर दिया।

मंत्री और सलाहकार ने आश्वासन दिया कि सरकार नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उन्होंने जनता से शांत रहने, अधिकारियों के साथ सहयोग करने और आधिकारिक सलाह का पालन करने की अपील की।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जमानत पर छूटने वाले विदेशियों के लिए नीति बनाने पर विचार करने को कहा

नई दिल्ली, 3 सितंबरः धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी एक विदेशी नागरिक के जमानत की अवधि तोड़कर फरार होने की जानकारी मिलने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी नीति की जरूरत पर जोर दिया है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि देश में अपराध करने वाले विदेशी नागरिक ''न्याय से भाग न पाएँ''।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल 4 दिसंबर को झारखंड उच्च न्यायालय के मई 2022 के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें आरोपी एलेक्स डेविड को जमानत दी गई थी।

26 अगस्त को जब मामला न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो पीठ ने कहा कि नाइजीरिया और भारत के बीच किसी नाइजीरियाई नागरिक को देश में आपराधिक कार्यवाही का सामना करने के लिए प्रत्यर्पित करने को लेकर कोई द्विपक्षीय संधि नहीं है। पीठ ने कहा,

''विशेष अनुमति याचिका का निपटारा किया जाता है, जिसमें जमानत रद्द करने के आदेश की पुष्टि की जाती है, लेकिन केंद्र सरकार को यह विकल्प खुला छोड़ दिया जाता है कि वह एक उपयुक्त नीति बनाए या आगे की कार्रवाई शुरू करे जो आवश्यक और उचित समझी जाए ताकि विदेशी नागरिक भारत में अपराध करने के बाद न्याय की राह से न भागें।''

डेविड पर धोखाधड़ी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सहित कई अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था।

उच्च न्यायालय द्वारा जमानत मिलने के बाद, उन्होंने शीर्ष अदालत में आदेश को चुनौती दी।

लेकिन शीर्ष अदालत को बताया गया कि डेविड जमानत की अवधि तोड़कर फरार हो गए हैं।

इसके बाद शीर्ष अदालत ने केंद्र से ऐसे मामलों में निर्धारित प्रक्रिया और दिशानिर्देशों के बारे में पूछा।

केंद्र ने एक हलफनामा दायर किया, जिसमें आपराधिक मामलों के संबंध में विदेश में जाँच और अनुरोध पत्र जारी करने, पारस्परिक कानूनी सहायता अनुरोध और समन, नोटिस और न्यायिक दस्तावेजों की तामील के लिए व्यापक दिशानिर्देशों की मौजूदगी का संकेत दिया गया।

पिछले साल 4 दिसंबर को, शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और केंद्र को अपने दिशानिर्देशों में सुझाए गए उचित उपाय करने का निर्देश दिया।

जब 26 अगस्त को मामला सुनवाई के लिए आया, तो केंद्र की ओर से उपस्थित वकील ने पीठ के समक्ष विदेश मंत्रालय के सलाहकार (कानूनी) द्वारा महाधिवक्ता को संबोधित एक पत्र प्रस्तुत किया।

पीठ ने पत्र की सामग्री दर्ज की, जिसमें लिखा था, ''हालांकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि भारत और नाइजीरिया के बीच द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के अभाव में, नाइजीरियाई अधिकारियों द्वारा अपने नागरिक का प्रत्यर्पण करने की संभावना नहीं है।'' पत्र में कहा गया है कि प्रत्यर्पण अनुरोध संबंधित नाइजीरियाई अधिकारियों को आगे भेजने के लिए ''पारस्परिकता के आश्वासन'' के आधार पर नाइजीरिया के अबुजा में भारतीय उच्चायोग को भेजा गया था।

इस संवाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत में आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहे नाइजीरियाई नागरिक के प्रत्यर्पण पर दोनों देशों के बीच कोई द्विपक्षीय संधि नहीं है, पीठ ने कहा कि याचिका को लंबित रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

'एचआईवी' मरीजों की सुविधा रोकना, अमानवीय?

'दक्षिण अफ्रीका' ऐसा मुल्क है जहां 'एचआईवी' मरीजों की संख्या सर्वाधिक है। मोटे तौर पर तकरीबन ढ़ाई लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। दक्षिण अफ्रीका के सामने एचआईवी पर नियंत्रण के लिए मात्र जरिया 'मुत अमेरिकी चिकित्सा सुविधा' मानी जाती रही है? जिसे पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बंद करके का ऐलान कर दिया गया। बंदी के निर्णय के कुछ घंटों बाद ही सुविधाएं भी रोक दी गईं। इससे निश्चित रूप से एचआईवी संक्रमितों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी होगी? होगी क्या, हो ही गई? सभी जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में एचआईवी संक्रमितों के लिए अमेरिका की मुत चिकित्सा सुविधा वर्षों से जारी थीं। सुविधा बंद करके अमेरिका ने अमानवीय चेहरे से परिचय कराकर दुनिया में थू–थू भी करा ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति को कोई ये बात समझाए कि इंसानी जीवन से बढ़कर कोई दौलत, कोई शौहरत नहीं होती? किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को मरीजों के जीवन से साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जीवन बचाने के लिए नफे–नुकासान की परवाह तो कतई नहीं करनी चाहिए।

चिकित्सा सहायता रूकने से एक साथ 2 लाख 22 हजार एड्स संक्रमितों के जीवन को नर्क में धकेला गया है। डोनाल्ड ट्रंप विभिन्न देशों पर अनाप–शनाप टैरिफ लगाना, बिलावजह की वंदिशें और कई वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने जैसे उंटपटांग निर्णयों को लेकर पहले से दुनिया के निशाने पर हैं। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका में एचआईवी पीड़ितों को मुत एचआईवी सेवाएं बंद करके सोचने पर मजबूर कर दिया है। ट्रंप के निर्णयों ने पूरी दुनिया में वैसे ही उथलपुथल मचाई हुई है। इस कड़ी में उन्होंने अफ्रीका के लाखों मरीजों का भी जीवन संकट में डाल दिया है। दक्षिण अफ्रीका सरकार भी हैरान है कि आखिर अमेंरिका ने ऐसा अमानवीय कदम उठाया क्यों? ट्रंप के फैसले के बाद मरीज

एचआईवी सुविधा केंद्रों पर दौड़े, लेकिन बिना दवाईयों के उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में एड्स पीड़ितों का अधि.त आंकड़ा जितना है उससे कहीं ज्यादा अनाधि.त है। मुत सुविधाएं रूकने के बाद गुप्त मरीजों की संख्याओं को देखकर सरकार भी हैरत में है।

मुत सुविधाएं क्यों रोकी गईं? इस गणित को समझना भी जरूर है। दरअसल, एचआईवी दवाओं की लागत दवा के प्रकार, भौगोलिक स्थिति और दवा कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के आधार पर भिन्न होती हैं। खरीद में एचआईवी की दवाईयां काफी महंगी पड़ती हैं। कीमतें विभिन्न देशों में अलग–अलग रहती हैं। जगहों के आधार पर दवाइयों में बदलाव भी होता है। भारत में, एचआईवी के लिए 'एंटीरेट्रवाइल थेरेपी' और 'एपरेटयूड इनजेक्शन' के अलावा 'ग्लाइड' इस्तेमाल की जाती है जिसके प्रत्येक बॉक्स की कीमत 23 हजार और 15 हजार होती है। बाकी अन्य देश 'टेनोफोविर', 'लेमिवाउडिन', 'डोल्यूटेग्राविर' भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एचआईवी संक्रमित पर 'न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिपटेस इनहिबिटर प्रोटीएस भी उपयोग होते हैं। ये सभी दवाइयां निजी स्तर पर महंगी होती हैं। बिना सरकारी सहायता के कोई आसानी से नहीं खरीद सकता। ज्यादातर देश अपने मरीजों को सब्सिडी देकर कम दामों में मुहैया करवाते हैं। भारत में भी ये दवाईयां बिल्कुल फ्री नहीं हैं। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर अमेरिका ने यह फैसला लिया।

दक्षिण अफ्रीका में मुफत दवाई वितरण में अमेरिका को सालाना करोड़ों रूपए का नुकसान हो रहा था। अमेरिका सालों से अफ्रीकी लोगों को एचआईवी ग्रस्तों को मुत चिकित्सा मुहैया करवाता आया था। पर, अब उसे घाटे का सौदा दिखने लगा? इसलिए मरीजों की जान की परवाह किए बिना ये गैरजरूरी निर्णय ले लिया। जबकि, उसे पता है कि एचआईवी पीड़ितों की सर्वाधिक संख्या इस समय दक्षिण अफ्रीका में है। अमेरिका शुरू से कहता आया था कि अफ्रीकी लोग संसार के दूसरे देशों में पहुंचते हैं तो वहां भी संक्रमण फैलाते हैं। ऐसा न हो, उसके लिए वह अपने स्तर से वहां फैले एचआईवी को नितंत्रण करने के लिए पीड़ितों का ईलाज करते थे। लेकिन, विगत सप्ताह अचानक निःशुल्क चिकित्सा सहायता पर विराम लगा दिया। जबकि, इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि ऐसा करने से एचआईवी संक्रमितों के जीवन पर बात बन आई है। एड्स के डर से मर–मर कर अपना जीवन जीने वाले मरीज इस सदमे कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। अमेरिका की इस हरकत ने मानवीय पहलूओं का भी अनादर किया है। बंदी के निर्णय के बाद मरीज लगातार क्लीनिकों की ओर दौड़ रहे हैं, भगदड़ जैसी स्थिति बनीं हुई है।

हैरान करने वाली बात ये है कि अमेरिका ने निर्णय अचानक लिया, अफ्रीकी सरकार को सूचित भी नहीं किया। 16 क्लीनिकों में 12 क्लीनिक बंद कर दिए जिनमें 63,000 से ज्यादा मरीज प्रभावित हुए हैं। शेष बचे 4 क्लीनिकों में भी जीवनरक्षक दवाईयां पहुंचनी बंद हो गईं हैं। इस बात का वैश्विक स्तर पर जमकर विरोध भी हो रहा है। अमेरिका पर पुर्नविचार की मांग उठ रही है। इतना तय है, अगर मदद जल्द बहाल नहीं हुई, तो न सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में लाखों एचआइवी पीड़ितों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि हजारों मौतें भी होनी आरंभ हो जाएंगी। 'गिलियड' एचआईवी पर नियंत्रण करने वाली प्रमुख दवाई मानी जाती है। गिलियड फार्मा कंपनी ने पिछले अक्टूबर–2024 में विश्व की 6 प्रमुख फार्मा कंपनियों के साथ समझौता किया था ताकि गरीब 120 देशों में ये दवा कम कीमत पर उपलब्ध हो। लेकिन कम कीमत के नाम पर ज्यादातर फार्मा कंपनियों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए।

बहरहाल, संक्रमितों के बचे–खुचे जीवन को बचाने के लिए दक्षिण अफ्रीकी सरकार को प्रतिबद्ध होना होगा। रोकी गई सुविधाओं की भरपाई का विकल्प खोजना होगा। सुखद खबर ये है कि फिलहाल, अमेरिका ने कुछ आवश्यक जीवनरक्षक सेवाओं को सीमित स्तर पर शुरू करने का आश्वासन दिया है। लेकिन संकट फिर भी बरकरार है, टला नहीं? क्योंकि अमेरिकी हुकूमत पर फिलहाल विश्वास नहीं किया जा सकता। दक्षिण अफ्रीका ने भारत जैसे अन्य देशों से भी मदद की गुहार लगाई है। पर, इस सच्चाई से सभी वाकिफ हैं कि एचआईवी निरोधक दवाइयों पर जो सफलता अमेरिका ने पाई है, वैसी किसी दूसरे देश ने नहीं? उनके पास इकाइयों का अच्छा बैकअप है। अफ्रीका को फ्री में शायद ही कोई देश दवाई देने पर राजी हो? इसलिए अफ्रीकी सरकार को अपने बजट में इजाफा कर एचआईवी पीड़ितों के लिए धन आवंटित करना चाहिए, ताकि विदेशों से दवाईयां खरीदी जा सकें। एचआईवी संक्रमण न फैले, इसके लिए जागरूकता अभियान भी छेड़े जाने की जरूरत है।

– डॉ. रमेश ठाकुर
सदस्य, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (छप्च्ब्व्), भारत सरकार!
(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

वैश्विक कूटनीति के 'मोदी मॉडल' से मचे अंतरराष्ट्रीय धमाल के मायने

कमलेश पांडे

वैश्विक कूटनीति के 'मोदी मॉडल' से एक के बाद एक मचे अंतरराष्ट्रीय राजनयिक धमाल के मायने ब्रेक के बाद निरंतर दिलचस्प होते जा रहे हैं, क्योंकि ये अमेरिकी नेतृत्व वाली एक ध्रुवीय दुनिया से इतर बहुपक्षीय दुनिया को कतिपय मामलों में ग्रेस प्रदान करते हैं। समकालीन दुनियादारी में अमेरिकी हैकड़ी पर लगाम लगाते हुए भारत ने रूसी–चीनी खेमे के द्विध्रुवीय दुनिया के साथ खड़े होने की जो चतुराई दिखाई है, वह इसलिए कि अंतरराष्ट्रीय तौर पर उपेक्षित, पददलित और पिछड़े देशों यानी ग्लोबल साउथ के दूरगामी हितों को साधा जा सके।

चूंकि अब पूरी दुनिया में चीन के नेतृत्व में आयोजित हुए एससीओ की बैठक से जुड़ी पीएम नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की आपसी पर्सनल केमिस्ट्री वाली तस्वीर वायरल हो चुकी है, इसलिए वैश्विक कूटनीतिक विशेषज्ञ उसका लगातार विश्लेषण कर रहे हैं और आए दिन बदलती दुनियादारी में अपनी माकूल जगह तलाश रहे हैं। जबकि भारत के साथ दोस्त बनकर गद्दारी की फितरत रखने वाला अमेरिका अब अपना सिर धुन रहा है।

चौंकाने वाली बात यह है कि लगातार भारत विरोधी विषबमन करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके आर्थिक सलाहकार पीटर के इतर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत–अमेरिकी संबंधों को फिर से संभालने की कोशिश की है। जिसके बाद केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का भी एक बयान सामने आया है जो सकारात्मक संदेश देता है कि ट्रेड डील के लिए अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है। हालांकि, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अमेरिकी हठधर्मिता सामने आई है, उसके .ष्टिगत भारत को अब चीन की तरह ही अमेरिका के साथ भी अपनी शर्तों पर फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि ये लोग भरोसे के लायक नहीं हैं, खासकर वैश्विक वफादार मित्र रूस की तरह।

अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि टैरिफ पर अड़ियल रुख के बावजूद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोग भरे पड़े हैं, जो अमेरिका के लिए भारत के रणनीतिक महत्व के विविध आयाम को समझते हैं। लिहाजा, मार्को रुबियो उनमें से ही एक हैं। देखा जाए तो उनका बयान ही नहीं, बल्कि उसकी टाइमिंग भी काफी अहम है। जिस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को एकतरफा बताया, उसी दिन रुबियो ने इस साझेदारी को 21वीं सदी का निर्णायक रिश्ता करार दिया। यही नहीं, उन्होंने दोनों देशों की जनता के बीच बनी मित्रता को इंडिया–यूएस पार्टनरशिप का आधार बताकर हाल में आई कटुता को एक हद तक दूर करने का जो प्रयास किया है, वह उनकी दूरदर्शिता और बौद्धिक परिपक्वता की निशानी है।

जानकार बताते हैं कि दुनियावी तौर पर वयोवृद्ध राष्ट्रपति ट्रंप की छवि एक ऐसे अड़ियल राजनेता की बन चुकी है, जिसकी आदतें और नीतियां अस्थिर हैं, और वो व्यक्तिगत पसंद–नापसंद के आधार पर बदलती रहती हैं। जो राष्ट्रपति ट्रंप कभी पीएम मोदी के लिए कुर्सियां लगाते व पकड़े दिखाई देते हैं, वहीं उनके लिए अपमानित करने वाली बात कहेंगे, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता है, लेकिन ट्रंप ने बिल्कुल वैसा ही किया है। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में भी कई ऐसे बयान दिए थे, जिनके बारे में बाद में व्हाइट हाउस को सफाई तक देनी पड़ी। चाहे भारत–पाकिस्तान के बीच कश्मीर मसले पर मध्यस्थता का प्रस्ताव हो या फिर अमेरिकी चुनाव में दखल के मामले में रूस को क्लीनचिट देना– ट्रंप ने अपने विदेश विभाग को कई बार असमंजस में डाल दिया था। वहीं, बंगलादेश में हिन्दू उत्पीड़न की उन्होंने जिस तरह से जबर्दस्त मुखालफत की, उससे हिन्दू बहुल देश भारत में उनसे सहानुभूति हुई। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और टैरिफ अटैक से जुड़ी शर्मनाक बयानबाजियों ने उनके तमाम सद्गुणों को धत्ता बता दिया।

वहीं अगर मौजूदा वैश्विक और द्विपक्षीय हालात को देखें, तो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भी अब भी कुछ वैसा ही होता दिखाई पड़ रहा है। भले ही ट्रंप का रवैया बातचीत के सारे रास्ते बंद करने का है, लेकिन अमेरिकी रणनीतिकार जानते हैं कि इससे चीजें और बिगड़ती चली जाएंगी। ऐसे में भारत की वैश्विक भूमिका को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इसलिए अमेरिकी प्रशासन अब गम्भीर हो चुका है। क्योंकि पश्चिमी मीडिया पीएम मोदी की चीन यात्रा और वहां पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन से हुई उनकी मुलाकात को अमेरिकी डिप्लोमैसी के लिए एक बड़े झटके के रूप में देख रहा है, जिससे उबरने में अब उसे वर्षों मेहनत करनी पड़ेगी।

हालांकि, भारत ने भी कूटनीतिक मामलों में हमेशा से ही चतुराई से काम लिया है, इसलिए उसने कभी भी द्विपक्षीय संवाद का रास्ता बंद नहीं किया है। हालिया केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। निःसन्देह दुनियाभर में कारोबारी रिश्तों का विस्तार करने के बावजूद भी नई दिल्ली ने वॉशिंगटन के साथ पुराने संबंधों को नहीं छोड़ा है। इस कड़ी में यह भी अहम है कि दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त अभ्यास के लिए अलास्का में जुटी हुई हैं।

भारत–अमेरिका दोनों पक्ष यही चाहते भी हैं कि बातचीत लगातार जारी रहे, क्योंकि दो दशकों की मेहनत के बाद उन्होंने अपने संबंधों को यह ऊंचाई दी थी। यह कड़वा सच है कि इस दौरान यह द्विपक्षीय रिश्ता कभी भी तीसरे देश को देखकर निर्धारित नहीं हुआ। इसलिए भारत ने फ्रांस, इंग्लैंड, जापान, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, ईरान, आसियान देश आदि सबसे घनिष्ठ सम्बन्ध विकसित किये। लिहाजा मौजूदा अनुभवी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को यह बात समझते हुए बातचीत के रास्ते खुले रखने चाहिए। उन्हें यह समझना होगा कि कुछ मामलों में ड्रैगन के व्यवहार से यूएस के बरक्स चीन के विश्वसनीय ताकत होने पर संदेह होता है, इसलिए अमेरिका का भविष्य उज्जवल हो सकता है, बशर्ते कि वह भारत को साधकर चल सके।

वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक
(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

वैश्विक राजनीति की बिसात पर ट्रंप को मोदी ही देंगे मात, अमेरिकी विशेषज्ञों ने कही है यह बात

नीरज कुमार दुबे

भारत–अमेरिका संबंधों पर हाल के घटनाक्रम गहरे द्वंद्व और भ्रम को उजागर करते हैं। एक ओर अमेरिकी रणनीतिक समुदाय के प्रभावशाली वर्ग, जैसे– जेक सुलिवन, मेरी किसल और एडवर्ड प्राइस बार–बार इस सच्चाई को रेखांकित कर रहे हैं कि चीन का प्रभाव अकेले अमेरिका की क्षमताओं से नियंत्रित नहीं किया जा सकता और इसके लिए भारत की साझेदारी अनिवार्य है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार इस साझेदारी को कमजोर करने वाला दिखाई देता है।

देखा जाये तो ट्रंप प्रशासन की ओर से भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी और इसे रूस से कच्चा तेल खरीदने से जोड़ना, रणनीतिक विवेक से अधिक राजनीतिक सनक का परिणाम प्रतीत होता है। एडवर्ड प्राइस की आलोचना इस संदर्भ में सार्थक है कि यह नीति न केवल अर्थशास्त्र और कूटनीति की गलत समझ दर्शाती है, बल्कि भारत को रूस और चीन के और निकट धकेलने का खतरा भी उत्पन्न करती है, जो अमेरिका की दीर्घकालिक विदेश नीति के लिए घातक परिणाम ला सकती है।

जेक सुलिवन का आरोप

इस परि.श्य को और जटिल बनाता है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन का वह आरोप जिसमें उन्होंने कहा है कि ट्रंप परिवार के पाकिस्तान में कारोबारी हितों के चलते भारत–अमेरिका संबंधों को बलि चढ़ाया जा रहा है। यदि इसमें सच्चाई का अंश भी है, तो यह अमेरिकी कूटनीति के लिए गंभीर संकट का संकेत है। ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन (ब्) जैसे मंचों पर रूस और चीन दोनों से सक्रिय संवाद कर रहे हैं, वाशिंगटन की असंगत नीतियां भारत के विकल्पों को और मजबूत करती हैं। हम आपको बता दें कि

जेक सुलिवन भारत–अमेरिका संबंधों के एक प्रमुख वास्तुकार रहे हैं। ऐसे में उनका यह आरोप बेहद गंभीर है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में अपने पारिवारिक कारोबारी हितों के चलते नई दिल्ली के साथ रिश्तों को नुकसान पहुँचाया है। हम आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन, जिन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन, बराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन के तहत पिछले एक दशक में कार्य किया है और जिनकी जिम्मेदारी में भारत से संबंध भी शामिल थे, उन्होंने सोमवार को पॉडकास्ट डमपकेंजवनबी में कहा कि ट्रंप ने "भारत के साथ रिश्तों को किनारे कर दिया है" क्योंकि पाकिस्तान ट्रंप परिवार के साथ कारोबारी समझौते करने को तैयार है।

सुलिवन का इशारा ट्रंप परिवार के उस संबंध की ओर था जो जैक विटकॉफ से जुड़ा है। हम आपको बता दें कि जैक विटकॉफ वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल (स्थ्) के सह–संस्थापक हैं, जिसने अप्रैल 2025 में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ एक समझौता किया था ताकि पाकिस्तान में क्रिप्टो विकास और डिजिटल वित्तीय परिवर्तन को बढ़ावा दिया जा सके। माना जाता है कि ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप, तथा दामाद जैरेड कुश्नर इस कंपनी में बड़ा हिस्सा रखते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि जैक, स्टीव विटकॉफ के बेटे हैं, जो ट्रंप के पुराने मित्र और दुनिया के विभिन्न हॉटस्पॉट क्षेत्रों (खाड़ी से लेकर रूस–यूक्रेन तक) में उनके सलाहकार रहे हैं। यह माना जा रहा है कि इसी क्रिप्टो डील के चलते ट्रंप ने पाकिस्तान के सैन्य शासक आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस आमंत्रित किया था, ठीक कुछ सप्ताह बाद जब जैक ने इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात कर अपना क्रिप्टो उपक्रम प्रस्तुत किया।

अमेरिका के पूर्व एनएसए जेक सुलिवन ने इसे "ट्रंप की विदेश नीति की सबसे कम रिपोर्ट की गई कहानियों में से एक" बताते हुए कहा कि भारत से संबंध तोड़ना "एक बड़ा रणनीतिक नुकसान" है। उनके अनुसार, इससे जर्मनी, जापान और कनाडा जैसे सहयोगी देशों का भरोसा भी डगमगा सकता है, क्योंकि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकेगा और वह मान सकते हैं कि अगला नंबर उनका है। उन्होंने कहा, "हमारा वचन ही हमारा बंधन होना चाहिए। हमारे मित्रों को हम पर भरोसा कर पाना चाहिए। भारत के साथ जो कुछ हो रहा है उसका असर केवल द्विपक्षीय संबंधों पर ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में हमारे साझेदारियों पर भी पड़ेगा।"

हम आपको यह भी बता दें कि अमेरिकी मीडिया में चीन में आयोजित एससीओ (ब्) शिखर सम्मेलन को लेकर व्यापक कवरेज हुआ और कई विशेषज्ञों ने अफसोस जताया कि ट्रंप की कठोर नीति भारत को रूस और चीन के और निकट धकेल रही है। इसे कुछ विश्लेषकों ने "अशांति की नई धुरी" तक कहा। हालाँकि, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने (ब्) बैठक को "ज्यादातर दिखावटी" करार देते हुए कहा कि भारत के मूल्य अमेरिका से कहीं अधिक मेल खाते हैं,

शेष भाग पृष्ठ 6 पर

एसआईआर की प्रक्रिया जारी रहने का आदेश स्वागतयोग्य

ललित गर्ग

बिहार में चुनाव आयोग की ओर से शुरू की गई मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया लगातार चर्चा में है। जहां एक तरफ इसे लेकर शुरू की गई कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा सोमवार को पटना में विपक्षी नेताओं की रैली के साथ समाप्त हुई, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर नए आदेश जारी करते हुए मतदाता सूची सुधार का कार्य आगे भी जारी रहने का निर्देश जारी किये हैं, यह निर्देश स्वागतयोग्य है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह पूरा प्रकरण आखिरकार कैसा मोड़ लेगा और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर किस तरह का असर डालेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को स्पष्ट कर दिया कि बिहार के मतदाता 1 सितंबर के बाद भी दावा या आपत्ति कर सकेंगे। यह निर्देश बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी राजनीतिक दलों की शिकायतें दूर नहीं हुई हैं। ज्यादातर आम लोगों की शिकायतों का निवारण कर दिया गया है, पर कुछ राजनीतिक पार्टियों के लिए एसआईआर की खामी एक बड़ा मुद्दा है। महागठबंधन में शामिल दल इस मुद्दे में विवाद खड़े करने में ही अपने चुनावी हित देख रहे हैं। हालांकि, न्यायालय ने उचित ही बताया है कि मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर असमंजस की स्थिति काफी हद तक 'विश्वास का मामला' है। इसका मतलब, जो राजनीतिक अविश्वास है, उसे दूर करने के लिए स्वयं दलों को सक्रिय होना पड़ेगा। न्यायालय की इस सलाह पर राजनीतिक दलों को गौर करना चाहिए और इस प्रक्रिया को सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि चुनाव सुधार एक सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर सभी राजनीतिक दल यह ठान लें, तो चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सकता है। वास्तव में, मतदाता पुनरीक्षण का काम राजनीतिक दलों को अपने स्तर पर लगातार जारी रखना चाहिए, इससे लोकतंत्र की मजबूती सुनिश्चित होगी एवं चुनाव की खामियों को सुधारा जा सकेगा।

वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर आयोजित रैली में विपक्षी नेताओं ने जो कुछ कहा, उससे स्पष्ट है कि चुनाव आयोग की ओर से शुरू की गई इस प्रक्रिया के औचित्य को लेकर वे अभी आश्वस्त नहीं हैं। वैसे इस तरह की संवैधानिक प्रक्रियाओं को भी राजनीतिक रंग देना, विडम्बनापूर्ण है। इससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है विपक्षी नेताओं द्वारा कथित वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए चुनाव आयोग को आरोपों के दायरे में शामिल रखा जाना। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी नेता चुनाव आयोग और सरकार को घेरते हुए यह मुद्दा बार–बार उठाते रहेंगे। विपक्षी दल इस विषय में जिस तरह की नकारात्मकता दर्शा रहे हैं, वह भी प्रश्नों के घेरों में एवं अतिश्योक्तिपूर्ण है। क्योंकि यह अत्यंत सामयिक और संवेदनशील है। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया, एक ओर मतदाता सूची को शुद्ध एवं पारदर्शी बनाने का प्रयास है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव द्वारा इस प्रक्रिया को चुनौती देते हुए 'वोटर अधिकार यात्रा' निकालना और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर प्रश्नचिह्न खड़ा करना, लोकतंत्र की सेहत और स्थायित्व को धुंधलाता है।

सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई का जहां तक सवाल है तो वहां भी विपक्षी दल और चुनाव आयोग एक–दूसरे पर तीखे आरोप लगाते नजर आए। जहां विपक्षी दलों के वकील इस प्रक्रिया की खामियों की ओर कोर्ट का ध्यान दिलाते रहे, वहीं चुनाव आयोग के वकील ने साफ शब्दों में कहा कि समस्या इस प्रक्रिया में नहीं, बल्कि उस मानसिक सोच में है, जो आग्रह, पूर्वाग्रह एवं दुराग्रह से ग्रस्त है। उनके मुताबिक दूसरे पक्ष की मानसिकता ही खोट निकालने की हो गई है। इसमें दो राय नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को यथासंभव उपयुक्त ढंग से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह देखना बाकी है कि चुनाव आयोग इस प्रक्रिया में सभी पक्षों का विश्वास जीतने और सभी योग्य मतदाताओं की आशंकाएं दूर करने में किस हद तक कामयाब हो पाता है।

निश्चित ही पुनरीक्षण की प्रक्रिया में अभी तक के अनुभव मिले–जुले रहे हैं। चुनाव आयोग की ओर से अदालत में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बताया कि राजनीतिक दल सूची में मतदाताओं को शामिल करने के दावों के बजाय उन्हें हटाने की मांग करते हुए आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं। अगर चुनाव आयोग ने ज्यादा नाम काटे होते, तो नाम जोड़ने के लिए ज्यादा दावे होते। कांग्रेस को शायद अभी भी शिकायत है कि उसके एजेंटों के दावे पर गौर नहीं किया गया है। दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने कहा है कि दावे यथोचित प्रारूप में नहीं किए गए हैं। ऐसे में, चुनाव आयोग को कुछ उदारता बरतते हुए अपनी सूची का हकीकत से मिलान करना चाहिए। बिहार में ही बड़ी पार्टियों के तमाम बूथ लेबल एजेंट (बीएलए) सक्रिय हो जाएं, तो मतदाता सूची को दोषरहित बना सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की भी यही मंशा है। मतदाता सूची को लेकर विवादों में पड़े रहना हर प्रकार से अफसोसजनक होगा, इससे हमारे लोकतंत्र की गरिमा घटेगी। गौर करने की बात है कि शीर्ष अदालत के निर्देश पर सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और पैरा लीगल स्वयंसेवकों को पुनरीक्षण में लगाया जाएगा। वास्तव में, पुनरीक्षण जल्दी संपन्न होना चाहिए, ताकि बिहार चुनाव में देरी न होने पाए।

चुनाव आयोग भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है। इसका दायित्व केवल चुनाव कराना नहीं, बल्कि चुनाव की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना भी है। मतदाता सूची में गड़बड़ी, डुप्लीकेट नाम, मृत व्यक्तियों के नाम, या फर्जी पंजीकरण जैसी समस्याएं अक्सर चुनावी निष्पक्षता पर प्रश्न उठाती रही हैं। ऐसे में एसआईआर जैसी प्रक्रिया को चुनाव आयोग द्वारा लागू करना आवश्यक कदम माना जा सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले पर्याप्त राजनीतिक परामर्श, जनजागरूकता और पारदर्शिता सुनिश्चित की गई थी? यदि ऐसा नहीं हुआ, तो राजनीतिक दलों का असंतोष स्वाभाविक है। इसमें कोई शक नहीं कि पुनरीक्षण के मामले ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। बिहार आज निर्णायक मोड़ पर है। विशेष रूप से जन सुराज पार्टी के जो तेवर हैं, उससे बिहारी राजनीति के पूरे कलेवर पर असर पड़ सकता है। बिहार का विकासोन्मुख होना जरूरी है। इस जरूरत को बिहार में नया और पुराना विपक्ष ही नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष भी नए सिरे से समझ रहा है। लोगों के लिए तो यही सबसे अच्छी बात होगी कि सभी राजनीतिक दल अपने मुद्दों में विकास और रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा को सबसे ज्यादा तरजीह दें।

अब बड़ा प्रश्न है कि यदि सुप्रीम कोर्ट आयोग के पक्ष में निर्णय देती है, तो विपक्ष को अपने आंदोलन का औचित्य सिद्ध करना कठिन होगा। वहीं यदि अदालत को प्रक्रिया में खामियां मिलती हैं, तो आयोग की कार्यप्रणाली पर गहरे प्रश्न उठेंगे। विपक्ष की ओर से इसे सीधे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताना भी अतिशयोक्ति कहा जा सकता है, क्योंकि मतदाता सूची को शुद्ध करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ही हिस्सा है। यदि ऐसे हर संवैधानिक कदम को राजनीतिक रंग देकर विवादित बना दिया जाए, तो लोकतंत्र में संस्थाओं की मजबूती के बजाय कमजोरी ही बढ़ेगी। एसआईआर जैसी पहल की केवल बिहार ही नहीं, समूचे देश में जरूरत है ताकि चुनाव प्रक्रिया भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों से मुक्त हो सके। लेकिन इसकी सफलता तभी सुनिश्चित होगी जब यह निष्पक्ष, पारदर्शी और सर्वसम्मत तरीके से लागू हो। चुनाव आयोग को न केवल अपने कदमों की संवैधानिकता, बल्कि उसकी जनस्वीकार्यता भी सुनिश्चित करनी चाहिए। विपक्ष को भी इस प्रक्रिया को मात्र राजनीतिक हथियार बनाने के बजाय रचनात्मक संवाद के जरिए समाधान तलाशना चाहिए। लोकतंत्र केवल मतदाताओं की भागीदारी से नहीं, बल्कि संस्थाओं पर विश्वास से भी जीवित रहता है। इसलिए संस्थाओं की गरिमा और पारदर्शिता दोनों की रक्षा अनिवार्य है।

लेखक, पत्रकार, स्तंभकार
(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

जरांगे भले खुद को जीता हुआ मान रहे, असली खेल तो फडणवीस ने कर दिया, मराठा आंदोलन के पर्दे के पीछे कौन?

अभिनय आकाश

सुबह तक माहौल गर्म था, शाम होते होते शांति स्थापित हो गई। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन वापस ले लिया गया है। लेकिन सवाल है कि ये स्वतःस्फूर्त था या कुछ तो है जिसकी परदादारी है। क्या ये सब एकनाथ शिंदे ने किया ताकी फडणवीस की दिक्कतें बढ़ाई जा सके। या इसके निशाने पर खुद शिंदे थे और ये कवायद इसके ठाकरे बंधुओं की साझी रणनीति थी। क्या शरद पवार की भी किसी तरह की भूमिका थी? आंदोलन वापस लेने के बाद मराठा एक्टिविस्ट मनोज जरांगे की आगे की रणनीति क्या है? इस पूरी कहानी का पटापेक्ष किस तरह से होगा। मनोज जरांगे ने काफी वक्त से आंदोलन छेड़ा हुआ था। इस आंदोलन को मराठा आरक्षण आंदोलन नाम दिया गया। कहा गया कि वो मराठाओं के आरक्षण के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। 29 अगस्त को वो इस प्रदर्शन को शुरू करते हैं। फिर 2 सितंबर को इस अनशन को खत्म कर दियाजाता है क्योंकि फडणवीस सरकार उनकी बात मान लेती है। लेकिन जरांगे ने आंदोलन खत्म करने के बाद इसे अपनी बड़ी जीत बताया।

आंदोलन की शुरुआत

1997 में मराठा आरक्षण के लिए पहला बड़ा आंदोलन है। मराठा महासंघ और मराठा सेवासंघ ने शुरुआत की। कहा गया कि मराठा कथित उच्च जातियों से नहीं बल्कि कुनबी समुदाय से आते हैं। मराठा को खेती– किसानी वाला समुदाय माना जाता है। 2008 से 2014 के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्रियों का मराठा आरक्षण की मांग को समर्थन किया। पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार और विलासराव देशमुख ने मराठा आरक्षण की मांग का समर्थन कर दिया। जून 2014 में पृथ्वीराज चौगान की सरकार ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिसके तहत सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में मराठों को 16 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। नवंबर 2014 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस आरक्षण पर रोक लगा दी।

कमीशन का गठन

जून 2017 में महाराष्ट्र सरकार ने मराठों की सोशल, एजुकेशनल और फाइनेंशियल स्टेटस की स्टडी के लिए स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन किया। नवबंर 2018 में कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा समुदाय को 16 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित हो गया। दिसंबर 2018 में इस कानून को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन था, जिसके मुताबिक 50 : रिजर्वेशन की सीमा तोड़ी नहीं जा सकती।

कोर्ट में तब क्या हुआ

जून 2019 में मराठों को आरक्षण देने वाले कानून की संवैधानिक वैधता पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। हालांकि इसे 17 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करने का सुझाव दिया गया। मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया।

जरांगे की एंट्री

2023 में इसमें एक अहम पड़ाव आया। जरांगे ने 29 अगस्त 2023 को जालना के अपने गांव में पहली बार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की। तब से ये उनका सातवां विरोध प्रदर्शन था। जरांगे ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कई विरोध रैलियां और भूख हड़तालें की थी। 20 फरवरी 2024 को एकनाथ शिंदे सरकार ने मराठों को 50 प्रतिशत की सीमा से उपर 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए एक विधेयक पेश किया। इस साल जनवरी में भी राज्य सरकार की ओर से भाजपा विधायक के हस्तक्षेप के बाद जरांगे ने छठे दिन भूख हड़ताल समाप्त कर दी। मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर मनोज जरांगे पाटिल सड़कों पर उतरे तो लेकिन उसमें उन्हें सिर्फ विपक्षी पार्टी के नेताओं का मिला। आम जनता को इस बात का पता है कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार पहले से ही आरक्षण दे रही है। 2024 की बात है। फडणवीस ने 10 फीसदी मराठा आरक्षण का बिल पास करवाया था। सुप्रीम कोर्ट में ये चौलेंज भी हो चुका है। जरांगे की मुख्य मांग ओबीसी कैटेगरी के तहत कुनबी स्टेटस थी। इससे मराठाओं को ओबीसी कोटा यानी 27 फीसदी में शामिल किया जा सकता है, जो ज्यादा फायदेमंद हैं। फडणवीस ने जरांगे को राजनीतिक बताते हुए उनकी आलोचना की थी। लेकिन इस बार कैबिनेट सब कमेटी ने इन मांगों को मान लिया।

विपक्ष को मिला मुद्दा

महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने हैं और उससे पहले अभी कोई मुद्दा हाल फिलहाल नजर नहीं आ रहा। महाराष्ट्र में तमाम हिंदुओं ने विधानसभा चुनाव में साबित कर दिया था। जो मौलाना ये चाहते थे कि जहां जहां बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा हो वहां हराया जाए, उन सब को जवाब दिया। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महायुति को जो प्रचंड बहुमत मिला। उद्धव ठाकरे को निराशा हाथ लगी। वो बताने के लिए काफी था कि महाराष्ट्र की जनता किसके साथ है। विपक्षी दलों की नेताओं की टेंशन बढ़ गई। बाला साहेब के सिद्धांतों को लेकर कहीं न कहीं मौजूदा सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र कई चीजों में आगे बढ़ता नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि विपक्षी दल को लगा कि चाहे लोकल लेवल के मुद्दे हो या बड़े स्तर के मसले हो, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे सरकार को घेरा जा सके।

मराठी बनाम हिंदी बनाने की कोशिश

कुछ दिन पहले मराठी बनाम हिंदी देखा गया। इसे जबरदस्त तरीके से मुद्दा बनाया गया। लेकिन उस मुद्दे को बहुत ही होशियारी के साथ देवेंद्र फडणवीस सरकार ने हैंडल कर लिया। उस मुद्दे को ज्यादा हाइप नहीं मिल पाया। जिस फैसले पर तंज कसा जा रहा था और मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही थी। उस फैसले को वापस लेते हुए फडणवीस सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। विपक्षी दलों के सारे मुद्दे धराशायी हो गए। फिर मैदान में जरांगे की एंट्री होती है। वो ये बताने की कोशिश में हैं कि मराठाओं की लड़ाई वही लड़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि लड़ लड़ाकर 2024 में खुद फडणवीस सरकार ने 10 प्रतिशत आरक्षण का बिल पास कराया था।

वैश्विक राजनीति की बिसात पर ट्रंप को मोदी ही देंगे मात, अमेरिकी विशेषज्ञों ने कही है यह बात

चीन या रूस से नहीं। उन्होंने कहा, "भारतीयों ने रूसी तेल खरीदकर और उसे दोबारा बेचकर यूक्रेन युद्ध को वित्तीय मदद दी है। लेकिन अंततः, दो महान राष्ट्र इस समस्या का समाधान कर लेंगे।"

व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भी भारत पर अपनी आलोचना को थोड़ा नरम करते हुए तियानजिन में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का हवाला देते हुए कहा, "मोदी को शी जिनपिंग और पुतिन के साथ देखना अफसोसजनक था३ हमें उम्मीद है कि वे समझेंगे कि उन्हें हमारे साथ होना चाहिए, न कि रूस के साथ।" फिर भी, कई विश्लेषकों का मानना है कि नुकसान हो चुका है और संबंधों को बहाल करना कठिन होगा। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ शोधकर्ता एडवर्ड प्राइस ने बताया, "भले ही भारत और अमेरिका अंततः टैरिफ पर कोई समझौता कर लें, लेकिन भरोसा खो चुका है।" उन्होंने चेतावनी दी, "यदि चीन, रूस और भारत किसी भी आर्थिक या आंशिक सैन्य गठबंधन में एकत्रित हो जाते हैं, तो अमेरिका के लिए 21वीं सदी में प्रतिस्पर्धा करना असंभव हो जाएगा। बेहतर होगा कि हम घर चले जाएँ।''

मैरी किसेल का बयान

वहीं, अमेरिका की पूर्व सलाहकार मैरी किसेल ने कहा है कि इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का अकेले अमेरिका मुकाबला नहीं कर सकता और इसके लिए भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वाशिंगटन को बीजिंग की बढ़ती ताकत का सामना करने के लिए नई दिल्ली का सहयोग चाहिए। हम आपको बता दें कि किसेल पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की वरिष्ठ सलाहकार रह चुकी हैं। उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिये साक्षात्कार में आर्थिक तनावों के बीच भारत–अमेरिका साझेदारी की मजबूती पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह तनाव वाशिंगटन द्वारा भारतीय आयात पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ और रूस से कच्चा तेल खरीदने पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क के कारण और बढ़ा है। किसेल ने कहा, "यदि हम सचमुच साम्यवादी चीन को अमेरिका और हमारी जीवनशैली के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं, तो हमें भारत की जरूरत है। यह सच्चाई है। हम एशिया–प्रशांत क्षेत्र में अकेले उनसे नहीं लड़ सकते।" किसेल ने यह भी कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत की सक्रिय भूमिका ट्रंप प्रशासन के लिए चीन की आक्रामकता से निपटने में बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। उन्होंने कहा, "हमें केवल ऑस्ट्रेलिया या जापान जैसे मित्रों की ही नहीं, बल्कि भारत की भी ताकत चाहिए। मेरा मानना है कि यह बैठक ट्रंप प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती को उजागर कर रही है।"

एडवर्ड प्राइस का साक्षात्कार

इसके अलावा, एक स्वतंत्र विदेश नीति विश्लेषक एडवर्ड प्राइस ने भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत–नीति पर कड़ी आलोचना की है और चेतावनी दी है कि हालिया व्यापारिक विवाद उस साझेदारी को कमजोर कर सकते हैं जिसे उन्होंने "21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी" बताया। एडवर्ड प्राइस न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में सहायक प्राध्यापक हैं। उन्होंने एक समाचार एजेंसी को दिये साक्षात्कार में कहा कि भारत पर ट्रंप के टैरिफ लगाने की धमकियाँ अर्थशास्त्र और कूटनीति, दोनों की बुनियादी समझ की कमी को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा, "मैं पहले सोचता था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अर्थशास्त्र और कूटनीति की बहुत खराब समझ है। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। असल में राष्ट्रपति ट्रंप को अर्थशास्त्र और कूटनीति की कोई समझ ही नहीं है।" देखा जाये तो यह आलोचना उस समय आई है जब ट्रंप ने ओवल ऑफिस में अपने बयान में भारत द्वारा अमेरिकी कंपनियों पर लगाए गए टैरिफ का उल्लेख किया, जबकि उसी समय उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका का भारत से "बहुत अच्छा तालमेल" है।

एडवर्ड प्राइस का कहना था कि भारत की टैरिफ नीतियाँ न्यायोचित हैं क्योंकि वह एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था ने विशेष रूप से विकासशील देशों को विकसित देशों की तुलना में अधिक टैरिफ लगाने की छूट दी थी। उन्होंने तर्क दिया कि ट्रंप की नीति रणनीतिक रूप से उलटी साबित हो रही है और भारत को चीन और रूस के करीब धकेल सकती है। उन्होंने कहा कि यह वही परिणाम है जिसे अमेरिकी विदेश नीति हमेशा टालना चाहती रही है। एडवर्ड प्राइस ने कहा कि हालिया तस्वीरें, जिनमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ दिखाई दिए, उसने इस संभावित उभरते गठबंधन को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

एडवर्ड प्राइस ने कहा, "ऐसा लगता है कि उन्होंने भारत को रूस और चीन के करीब ला दिया है।" हालाँकि, उन्होंने यह भी चेताया कि इन देशों के बीच ऐतिहासिक तनावों के कारण यह गठजोड़ स्थायी न होकर सामरिक हो सकता है। उन्होंने मोदी की चीन और रूस से सहभागिता को वॉशिंगटन के लिए एक सोची–समझी याद दिलाने की रणनीति बताया कि भारत के पास विकल्प मौजूद हैं। उन्होंने कहा, "मोदी समझदार हैं। मोदी अपने पत्ते खेल रहे हैं। वह अमेरिका को याद दिला रहे हैं कि उनके पास चुनाव का विकल्प है।" प्राइस ने यह भी कहा कि भारत का ऐतिहासिक झुकाव गुटनिरपेक्षता की ओर रहा है, जो शीतयुद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन में उसकी नेतृत्वकारी भूमिका से स्पष्ट है। इसलिए संभावना है कि नई दिल्ली महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा में स्थायी रूप से किसी एक पक्ष को न चुने।

पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन के उस आरोप पर कि पाकिस्तान में ट्रंप के व्यावसायिक हितों ने नीति को प्रभावित किया है, एडवर्ड प्राइस ने कहा कि राष्ट्रपति के सक्रिय वित्तीय हित चिंताजनक हैं जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने परंपरागत रूप से टाला है। साक्षात्कार में ट्रंप समर्थक पीटर नवारो की उस विवादित टिप्पणी पर भी चर्चा हुई जिसमें उन्होंने यूक्रेन युद्ध को "मोदी का युद्ध" कहा था। एडवर्ड प्राइस ने नवारो की विश्वसनीयता को खारिज करते हुए कहा कि ऐसी बयानबाजी "अजीब" है और जोर देकर कहा कि यह "पुतिन का युद्ध है, मोदी का नहीं।" प्राइस ने तर्क दिया कि 21वीं सदी में निर्णायक भूमिका भारत की होगी। अमेरिका और चीन के बीच शक्ति–संघर्ष के नतीजे का निर्धारण भारत की स्थिति से होगा।

प्राइस ने मौजूदा तनावों को उलटने के लिए दो ठोस कदम सुझाए। भारत पर लगाए गए 50ः टैरिफ की धमकी को खत्म कर शून्य टैरिफ लागू करना और औपचारिक रूप से माफी माँगना। उन्होंने कहा, "मैं समझ नहीं पा रहा कि अमेरिका का राष्ट्रपति, जब चीन से टकराव और रूस से युद्ध की स्थिति में है, तब भारत पर 50ः टैरिफ लगाने की बात क्यों करेगा।" देखा जाये तो यह आकलन विदेश नीति विशेषज्ञों के बीच इस चिंता को रेखांकित करता है कि यदि भारत–अमेरिका व्यापारिक तनाव यूँ ही जारी रहे, तो दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग पर गहरा असर पड़ सकता है।

इसके अलावा, कूटनीतिक वास्तविकता यह है कि भारत हमेशा से रणनीतिक स्वायत्तता और गुटनिरपेक्षता पर जोर देता आया है। मोदी का रूस और चीन के साथ संवाद इसी परंपरा का विस्तार है, न कि किसी स्थायी धुरी का निर्माण। किंतु यह भी सच है कि अमेरिका का असंगत और टकरावपूर्ण रवैया भारत को यह स्मरण कराने का अवसर देता है कि उसके पास विकल्प मौजूद हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या अमेरिका इस साझेदारी की वास्तविक अहमियत समझ पाएगा। यदि वह सचमुच चीन को अपनी सबसे बड़ी चुनौती मानता है, तो उसे भारत के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्तों में विश्वास बहाली करनी होगी।

बहरहाल, भारत आज 21वीं सदी की शक्ति–समीकरण का निर्णायक खिलाड़ी है। ऐसे में अमेरिका को यह भूलना नहीं चाहिए कि संबंध केवल बयानों से नहीं, बल्कि भरोसे और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता से बनते हैं। यदि अमेरिका इस बुनियादी तथ्य की अनदेखी करता है, तो उसकी एशिया–प्रशांत रणनीति महज खोखला नारा बनकर रह जाएगी।

–नीरज कुमार दुबे
(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

रुपया पांच पैसे टूटकर 88.15 प्रति डॉलर के नए सर्वकालिक निचले स्तर पर

नई दिल्ली 3 सितंबर। भारत–अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता और घरेलू शेयर बाजारों में कमजोरी से अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में मंगलवार को रुपये पर दबाव बना रहा और यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पांच पैसे गिरकर 88.15 के सर्वकालिकनिचले स्तर पर बंद हुआ।

विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि अमेरिका के बढ़े हुए शुल्क को लेकर फैली अनिश्चितता के बीच रुपया अबतक के सबसे निचले स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है और इसके नीचे जाने का जोखिम बना हुआ है। इसके अलावा, घरेलू शेयर बाजारों से लगातार विदेशी पूंजी की निकासी या डॉलर की मजबूती आगे भी रुपये की कमजोरी को बढ़ा सकती है।

सोमवार को कारोबार के दौरान रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 88.33 के अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर आ गया था। अंतरबैंक विदेशीमुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.14 पर कमजोर खुला और कारोबार के दौरान 88.20 के निचले स्तर तक गया।

कारोबार के अंत में यह 88.15 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव से पांच पैसे की गिरावट है। सोमवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.10 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ शोध विश्लेषक दिलीप परमार ने कहा, ''रुपये ने अपनी अधिकांश दिन के कारोबार में हुई बढ़त को गंवा दिया। ऐसा जोखिम से बचने की प्रवृत्ति और आयातित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण हुआ।

बाजार में आयातकों की ओर से डॉलर की भारी मांग देखी गई, जबकि विदेशी पूंजी की निकासी के बीच मुद्रा की आपूर्ति सीमित रही।'' दुनिया की छह प्रतिस्पर्धी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को मापने वाला, डॉलर सूचकांक 0.63 प्रतिशत की तेजी के साथ 98.38 पर जा पहुंचा। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा कारोबार में 1.80 प्रतिशत बढ़कर 69.38 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

मिराए एसेट शेयरखान के शोध विश्लेषक (मुद्रा एवं जिंस) अनुज चौधरी ने कहा, ''हमारा अनुमान है कि रुपया थोड़ा नकारात्मक रुख के साथ कारोबार करेगा क्योंकि व्यापार शुल्क को लेकर अनिश्चितता और कमजोर घरेलू बाजार स्थानीय मुद्रा पर दबाव डाल सकते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों की निकासी और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से भी घरेलू मुद्रा पर दबाव पड़ सकता है।''

मुद्रा कारोबारी अमेरिका के विनिर्माण पीएमआई आंकड़ों से संकेत ले सकते हैं। चौधरी ने कहा कि इस हते अमेरिका से आने वाली गैर–.षि पेरोल रिपोर्ट से पहले निवेशक सतर्क रह सकते हैं।

घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 206.61 अंक गिरकर 80,157.88 अंक पर बंद हुआ, जबकि निटी 45.45 अंक गिरकर 24,579.60 अंक पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक पूंजी बाजार में शुद्ध बिकवाल रहे। उन्होंने मंगलवार को 1,159.48 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों की बिक्री की।

इस बीच, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत अमेरिका के साथ एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत कर रहा है। दोनों देश मार्च से ही इस पर वार्ता कर रहे हैं और अब तक पांच दौर हो चुके हैं। अभी तक छठे दौर की वार्ता के लिए कोई नई तारीख तय नहीं हुई है।

साइबर सेंधमारी के कारण जगुआर लैंड रोवर का उत्पादन और खुदरा परिचालन हुआ बाधित

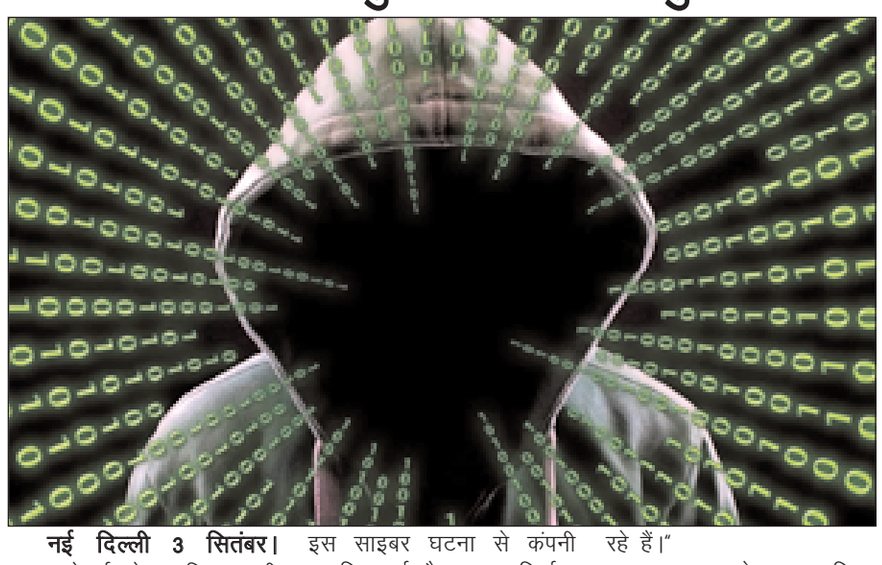

नई दिल्ली 3 सितंबर। टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली जगुआर लैंड रोवर ने मंगलवार को बताया कि साइबर सेंधमारी के कारण कंपनी की खुदरा और उत्पादन गतिविधियों में व्यवधान उत्पन्न हुआ।

ब्रिटिश ब्रांड जगुआर लैंड रोवर ने एक बयान में बताया कि इस साइबर घटना से कंपनी प्रभावित हुई है। वाहन निर्माता ने एक बयान में बताया, "हमने अपने सिस्टम को बंद कर इसके प्रभाव को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई की। अब हम अपने वैश्विक ऐप्लीकेशन को नियंत्रित तरीके से पुनः शुरू करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं।"

बयान के मुताबिक, फिलहाल इस बात का कोई सबूत नहीं है कि किसी ग्राहक का डेटा चोरी हुआ या नहीं, लेकिन खुदरा और उत्पादन गतिविधियां बुरी तरह बाधित हुई हैं।

दुबई से कितना सोना लाने पर लगता है जुर्माना, रान्या राव को भरने पड़े रु102 करोड़

नई दिल्ली 3 सितंबर। दुबई को गोल्ड का शहर कहा जाता है. यहां सोना भारत के मुकाबले 8 से 9 फीसदी तक सस्ता मिलता है. यही वजह है कि जो लोग दुबई घूमने या काम से जाते हैं, वो अक्सर वहां से सोना खरीदकर भारत लाने की सोचते हैं. लेकिन जरा रुकिए३ ऐसा करना आसान तो है, मगर कुछ शर्तों के साथ. हाल ही में एक मामला सामने आया है, जिसने सबका ध्यान खींचा है. कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री रान्या राव को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सोना तस्करी के आरोप में गिरतार किया गया. उनके पास से करीब 15 किलो सोना मिला. अब उन पर 102 करोड़ रुपये से ज़्यादा का जुर्माना लगाया गया है. मामला बड़ा है और सबक देने वाला भी.

दुबई में 24 कैरेट सोने की कीमत फिलहाल करीब 85–88 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम है. भारत में यही सोना इससे करीब 89: महंगा पड़ता है. इस फर्क को देखते हुए बहुत से लोग समझते हैं कि दुबई से सोना लाकर भारत में बचत की जा सकती है. लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि दुबई से सोना लाना तभी फायदेमंद होता है, जब आप सरकार के बनाए नियमों के हिसाब से चलें. अगर आपने तय सीमा से ज़्यादा सोना बिना बताए लाया, तो यही सोना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है.

अगर आप विदेश, खासकर दुबई से भारत लौट रहे हैं और सोना लाने की सोच रहे हैं, तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि इसके लिए भारत सरकार ने कुछ साफ–साफ नियम बना रखे हैं. तय सीमा के अंदर सोना लाने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन अगर आप तय मात्रा से ज्यादा सोना लाते हैं, तो आपको कस्टम ड्यूटी यानी टैक्स चुकाना होता है.

भारत सरकार के नियमों के मुताबिक, अगर आप भारतीय नागरिक हैं, तो पुरुष यात्री 50,000 रुपये तक के सोने के गहने बिना टैक्स के ला सकते हैं. महिलाओं के लिए यह सीमा 1 लाख रुपये तक है. वहीं, 15 साल से कम उम्र के बच्चों को भी इतनी ही छूट दी जाती है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह छूट सिर्फ गहनों पर लागू होती है. जैसे चेन, अंगूठी, झुमके या कड़ा. सोने की ईंट या सिक्कों पर यह नियम नहीं लागू होता.

इसके अलावा, आपके पास सोना खरीदने का पक्का बिल होना जरूरी है. बिना बिल के लाया गया सोना जब्त भी हो सकता है और जुर्माना भी लग सकता है. इसलिए अगर आप दुबई से सोना लाना चाहते हैं, तो नियमों की पूरी जानकारी रखनी चाहिए. थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए भारी नुकसान और कानूनी झंझट का कारण बन सकती है.

ज़्यादा सोना लाना है तो टैक्स चुकाना होगा

अगर आप तय सीमा से ज़्यादा सोना लाते हैं, तो फिर कस्टम ड्यूटी देनी होगी. सोना लाने वाले पर टैक्स कितना लगेगा, ये इस बात पर तय होता है कि आपने कितना सोना लाया है. अगर आप 6 महीने या उससे ज़्यादा समय तक विदेश में रहे हैं, तो आप एक किलो तक सोना चेक–इन बैग में लाकर कस्टम में घोषित कर सकते हैं. इसके लिए आपको टैक्स देना होगा.

जैसे अगर कोई आदमी 20 से 50 ग्राम सोना लाता है, तो उस पर 3 फीसदी टैक्स लगेगा. 50 से 100 ग्राम तक लाने पर 6 फीसदी और 100 ग्राम से ज़्यादा लाने पर 10 फीसदी टैक्स देना होगा. महिलाओं और बच्चों के लिए ये सीमा दोगुनी होती है.

लेकिन ये सब तभी संभव है, जब आपके पास खरीद का बिल हो और आप कस्टम ऑफिसर को सही जानकारी दें. अगर आपने चोरी–छिपे सोना लाने की कोशिश की, तो टैक्स के अलावा भारी जुर्माना और जेल भी हो सकती है.

गलती पड़ सकती है भारी

अभिनेत्री रान्या राव का मामला इसकी ताजा मिसाल है. उन्होंने तय सीमा से बहुत ज़्यादा सोना लाने की कोशिश की, वो भी बिना कस्टम में बताए. अब उन्हें न सिर्फ जेल की हवा खानी पड़ी, बल्कि 102 करोड़ से ज़्यादा का जुर्माना भी देना पड़ रहा है. अगर वो नहीं भर पाईं, तो उनकी संपत्ति जब्त हो सकती है. इससे साफ है कि सोना भले सस्ता हो, लेकिन अगर आप नियमों का पालन नहीं करते, तो ये बचत भारी नुकसान में बदल सकती है.

दुबई से सोना लाना कानूनन मुमकिन है. सस्ता भी पड़ सकता है. लेकिन इसके लिए आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए.कितना ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, और क्या बिल दिखाना जरूरी है. अगर आप तय सीमा में रहते हैं और सही तरीके से ड्यूटी भरते हैं, तो सोना लाना एक फायदे का सौदा बन सकता है. लेकिन अगर आप रास्ता गलत चुनते हैं, तो ये सोना आपको जेल तक ले जा सकता है.

जीएसटी परिषद की बैठक: आम आदमी को राहत! 2 स्लैब में बदल सकती है कर व्यवस्था

जीएसटी में बदलाव का किसानों को मिलेगा जबरदस्त फायदा, ये सभी सामान हो जाएंगे सस्ते

नई दिल्ली 3 सितंबर। जीएसटी परिषद की दो दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में अपने महत्वाकांक्षी सुधार के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर 5 प्रतिशत कर लगाने पर जोर दे सकती है। इस सुधार का उद्देश्य मक्खन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर कर की दरें कम करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में और राज्यों के वित्त मंत्रियों की भागीदारी वाली यह परिषद इस सत्र के दौरान इस प्रस्ताव पर विचार–विमर्श करेगी। 4 सितंबर को बैठक के समापन पर अंतिम निर्णय की घोषणा होने की उम्मीद है।

केंद्र का प्रस्ताव जीएसटी को सरल बनाने के लिए मौजूदा 12 और 28 प्रतिशत की स्लैब से उत्पादों को हटाकर केवल दो कर दरें 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत करने का है। इसके अलावा, विलासिता और अवगुण वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत की विशेष दर का सुझाव दिया गया है। इस कदम से कई आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम होने की उम्मीद है, हालाँकि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य किसी भी राजस्व हानि के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं।

जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्र और राज्य के वित्त मंत्री जीएसटी सुधारों के एक ही एजेंडे पर चर्चा के लिए एकत्रित हुए, जिसमें दरों को युक्तिसंगत बनाना, सरल अनुपालन और संभावित नए मुआवजा तंत्र शामिल हैं। परिषद की बैठक से पहले जमीनी स्तर पर तैयारी के लिए मंगलवार को अधिकारियों की एक बैठक हुई। 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की वर्तमान चार–स्तरीय जीएसटी संरचना 1 जुलाई, 2017 को लागू की गई थी, जिसने उत्पाद शुल्क और वैट जैसे कई राज्य और केंद्रीय करों की जगह ली थी। राज्यों को राजस्व की कमी को पूरा करने में मदद के लिए एक क्षतिपूर्ति उपकर भी शुरू किया गया था। हालाँकि, यह व्यवस्था जून 2022 में समाप्त हो गई।

15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधार योजना की घोषणा की। बाद में, केंद्र ने मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) के साथ एक खाका साझा किया, जिसने अनुपालन को आसान बनाने और उपभोक्ता कीमतों को कम करने के लिए 12 और 28 प्रतिशत की कर दरों को हटाने का व्यापक रूप से समर्थन किया।

किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. केंद्र सरकार की ओर से की जा रही ळेज संरचना में बदलाव का सीधा लाभ अब देश के करोड़ों किसानों तक पहुंचेगा. ट्रैक्टर, .षि उपकरण, सिंचाई साधन और खाद जैसे जरूरी सामान अब सस्ते होने की संभावना है. जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक से पहले ही संकेत मिलने लगे हैं कि .षि क्षेत्र से जुड़े कई सामानों पर टैक्स में बड़ी कटौती की जा सकती है.

अब तक किसानों को ट्रैक्टर और उससे जुड़े उपकरण खरीदते समय भारी जीएसटी देना पड़ता था, लेकिन नए प्रस्तावों के मुताबिक अब ट्रैक्टर पर केवल 5% जीएसटी लगेगा. यही नहीं, बीज ड्रिल, थ्रेशर, हैरो और अन्य .षि उपकरणों पर भी टैक्स दरों में कमी संभव है. सिंचाई उपकरणों पर भी 5% जीएसटी लागू करने की तैयारी है. इससे खेती में लगने वाली पूंजी लागत घटेगी और किसानों को राहत मिलेगी.

उर्वरक उद्योग से जुड़ी एक बड़ी मांग पर भी अब केंद्र सरकार विचार कर रही है. फर्टिलाइजेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FAI) ने सरकार से अनुरोध किया है कि अमोनिया और सल्यूरिक एसिड पर लगने वाला जीएसटी 18: से घटाकर 5: किया जाए. ये दोनों रसायन डाई–अमोनियम फॉस्फेट (DAP) और मिक्सड न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर के निर्माण में मुख्य कच्चा माल हैं.

FAI का कहना है कि जब तैयार खाद पर केवल 5: जीएसटी है, तो इनपुट यानी कच्चे माल पर 18% टैक्स आर्थिक रूप से असंतुलन पैदा करता है. इससे कंपनियों की इनपुट लागत बढ़ती है और अंततः यह बोझ किसानों पर पड़ता है. यदि सरकार इनपुट पर टैक्स घटाती है, तो बाजार में खाद की कीमतें घट सकती हैं, जिससे किसानों को सीधा फायदा मिलेगा.

इनपुट टैक्स क्रेडिट बना बड़ी चिंता

FAI ने यह भी बताया है कि इनपुट पर ज्यादा टैक्स और आउटपुट पर कम टैक्स की वजह से कंपनियों के पास भारी मात्रा में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) जमा हो गया है, जिसका उपयोग वे नहीं कर पा रही हैं. संगठन के अनुसार, यह अप्रयुक्त क्रेडिट लगभग 5,500 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. यदि सरकार इसका रिफंड नहीं करती, तो यह उर्वरक कंपनियों की वर्किंग कैपिटल पर दबाव बना सकता है और समय पर उत्पादन व आपूर्ति में रुकावट आ सकती है.

बता दें FAI का एक प्रतिनिधिमंडल 26 अगस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिला था और जीएसटी दरों में बदलाव की मांग रखी थी . इस प्रतिनिधिमंडल में इंडियन पोटाश लिमिटेड के एमडी पी. एस. गहलोत, कोरोमंडल इंटरनेशनल के एमडी और सीईओ एस. शंकरसुब्रमण्यन, और FAI के महानिदेशक सुरेश कुमार चौधरी शामिल थे. उन्होंने आग्रह किया कि 3–4 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर ठोस निर्णय लिया जाए.

FAI ने सरकार को यह भी बताया कि जीएसटी ढांचे में सब्सिडी को टैक्सेबल सप्लाई से अलग रखा गया है, जिसकी वजह से इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटपुट टैक्स के बीच बड़ा अंतर पैदा हो रहा है. इससे पूरी उर्वरक इंडस्ट्री वित्तीय असंतुलन का सामना कर रही है.

भारत के लिए तिजोरी खोलकर बैठा अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक, किया ये बड़ा ऐलान

अमेरिका के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी ने भारत के लिए अपनी तिजोरी खोल दी है. वो भी ऐसे समय पर जब अमेरिका के ही राष्ट्रपति ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है. साथ ही भारत को एक डेड इकोनॉमी करार दिया है. इन सब के बाद भी जेपी मॉर्गन भारत की इकोनॉमी और बढ़ते कदमों पर लगातार विश्वास जमाए हुए है.

इससे पहले अमेरिकी इंवेस्टमेंट फर्म मॉर्गन स्टानले ने भी भारत की इकोनॉमी पर विश्वास दिखाया था. अमेरिकी बैंक, इंवेस्टमेंट फर्म और रेटिंग एजेंसीज जिस तरह से भारत की इकोनॉमी पर भरोसा दिखा रही हैं, उससे साफ है कि वो ट्रंप की पॉलिसी और लिए गए फैसलों की परवाह नहीं करती. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर अमेरिका के सबसे बड़े बैंक के हेड ने मुंबई में एक इंटरव्यू के दौरान किस तरह की जानकारी दी है.

जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी भारत में अपनी कॉर्पोरेट बैंकिंग मौजूदगी को मजबूत कर रही है और ईवी, डाटा सेंटर और सोलर एनर्जी जैसे सेक्टर पर फोकस कर रही है. इसका कारण भी है. इन उद्योगों की कंपनियां देश इकोनॉमी में अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगातार इजाफा कर रही हैं. अमेरिकी बैंक में एशिया प्रशांत क्षेत्र में ग्लोबल कॉर्पोरेट बैंकिंग के को–हेड, ओलिवर ब्रिंकमैन ने हाल ही में मुंबई में एक इंटरव्यू में कह कि जैसे–जैसे डिमांड में सर्टेनिटी बढ़ेगी, कैपिटल इंवेस्टमेंट भी शुरू होगा.

जेपी मॉर्गन, जो कॉर्पोरेट बैंकिंग से रेवेन्यू के मामले में भारत और जापान को अपने दो सबसे तेजी से बढ़ते एशियाई बाजारों में गिनता है, को उम्मीद है कि वाशिंगटन द्वारा कई भारतीय आयातों पर टैरिफ को दोगुना करके 50 फीसदी करने के बावजूद विकास में कोई कमी नहीं आएगी. हालांकि पिछली तिमाही में भारत की ग्रोथ रेट 5 तिमाहियों की ऊंचाई पर पहुंच गया था. वहीं अर्थशास्त्रियों को चिंता बढ़ रही है कि टैरिफ श्रम–प्रधान उद्योगों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं और ग्रोथ स्लो हो सकती है.

सिंगापुर बेस्ड ब्रिंकमैन के अनुसार टैरिफ के साथ जियो पॉलिटिकल माहौल काफी जटिल है, लेकिन जेपी मॉर्गन का भारत में अपने कारोबार का .ष्टिकोण लॉन्गटर्म है. उन्होंने कहा कि बैंक की स्थानीय कॉर्पोरेट बैंकिंग पिछले दो–तीन सालों से साल–दर–साल अपने रेवेन्यू में 30: की वृद्धि कर रही है और उन्हें अगले कुछ वर्षों में भी इसी तरह की वृद्धि की उम्मीद है. एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने जून में एक रिपोर्ट में कहा था कि भारतीय कंपनियों द्वारा विकास के अवसरों की तलाश में अगले 5 सालों अपने कैपेक्स को पिछले 5 सालों की तुलना में दोगुना करके 800 बिलियन डॉलर से 850 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का अनुमान है. ब्रिंकमैन ने कहा कि हम सस्टेनेबल एनर्जी, डेक, इंडस्ट्रीज और इंफ्रा में अपनी कॉर्पोरेट बैंकिंग उपस्थिति का विस्तार करना चाहते हैं. उन्होंने आगे कहा कि जेपी मॉर्गन इन सेक्टर्स पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने घरेलू कर्मचारियों की संख्या बढ़ा रहा है.

भारत में बैंक के क्लाइंट सेगमेंट में मिड–कैप कंपनियां और लार्ज–कैप कंपनियां शामिल हैं, जिनका रेवेन्यू 30 करोड़ डॉलर से 2 अरब डॉलर के बीच है. देश में लगभग 1,900 क्लाइंट को सर्विस देने वाली इस अमेरिकी कंपनी की एक टीम स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न पर भी फोकस कर रही है. भारत में जेपी मॉर्गन का कारोबार कमर्शियल और इंवेस्टमेंट बैंकिंग, पेमेंट और सिक्योरिटीज सर्विसेज तक फैला हुआ है. इसके अलावा, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में कंपनी के कॉर्पोरेट सेक्टर्स 55,000 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं. यद्यपि भारत में कॉर्पोरेट बैंकिंग के लिए अवसर महत्वपूर्ण हैं, प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है, और कुछ प्रतिद्वंद्वी अधिकारी भविष्य को लेकर सतर्क बने हुए हैं.

पिछले महीने, बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प के एक सीनियर भारतीय अधिकारी ने कहा था कि घरेलू डिमांड और ग्लोबल ट्रेड सिनेरियो पर स्पष्टता आने तक कंपनियां बड़े निवेश निर्णय लेने से बच रही हैं. इस बीच, ब्लूमबर्ग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप इंक और सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप ने 2020 और 2024 के बीच भारतीय उधारकर्ताओं के लिए फॉरेन करेंसी लोन की व्यवस्था करने में अमेरिकी लेंडर्स पर बड़ी बढ़त हासिल की है. इस साल अब तक, जेपी मॉर्गन लिस्ट में 18वें पायदान पर है.

कुलदीप और अर्शदीप टीम से बाहर, इसलिए लिया गया ये फैसला

नई दिल्ली 3 सितंबर। चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह टीम से बाहर हो गए हैं. जी नहीं, हम यहां उनके एशिया कप की टीम इंडिया से बाहर होने की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं. बल्कि, एशिया कप के चलते उन दोनों के दलीप ट्रॉफी की टीम से बाहर होने की बात कर रहे हैं. दलीप ट्रॉफी में कुलदीप यादव सेंट्रल जोन से खेल रहे थे. जबकि अर्शदीप सिंह नॉर्थ जोन की टीम का हिस्सा थे. मगर अब ये दोनों दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में अपनी–अपनी टीमों से खेलते नहीं दिखेंगे.

कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह, दोनों ही एशिया कप में टीम इंडिया का हिस्सा हैं. और इन्हें 4 सितंबर को दुबई के लिए रवाना होना है. 4 सितंबर से ही दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल के मुकाबले हैं. यही वजह है कि कुलदीप यादव ना तो सेंट्रल जोन से और ना ही अर्शदीप सिंह नॉर्थ जोन से खेलते दिखेंगे. दलीप ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में नॉर्थ जोन को साउथ जोन से खेलना है. जबकि दूसरे सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन की टीम का मुकाबला वेस्ट जोन से होगा.

दलीप ट्रॉफी का क्वार्टर फाइनल खेले थे कुलदीप–अर्शदीप

कुलदीप और अर्शदीप दोनों ने ही दलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में अपनी–अपनी टीमों का प्रतिनिधित्व किया था. अर्शदीप सिंह ने ईस्ट जोन के खिलाफ खेले क्वार्टर फाइनल में 17 ओवर गेंदबाजी की थी, जिसमें 51 रन देकर 1 विकेट लिया था. वहीं कुलदीप यादव ने सेंट्रल जोन की तरफ से नॉर्थ–ईस्ट जोन के खिलाफ खेले दूसरे सेमीफाइनल में 20 ओवर गेंदबाजी की थी, जिसमें 55 रन दिए थे.

अब ये दोनों खिलाड़ी एशिया कप में फिर से एक बार भारत के दबदबे की कहानी लिखने उतरेंगे. कुलदीप यादव का ये पहला T20 एशिया कप होगा. वहीं अर्शदीप सिंह दूसरी बार T20 एशिया कप में खेलने उतरेंगे. इससे पहले अर्शदीप ने साल 2022 में T20 एशिया कप खेला था, जिसमें उन्होंने 5 मैचों में 5 विकेट लिए थे.

सुपर–4 में कोरिया से भिड़ेगा भारत, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड

नई दिल्ली 3 सितंबर। हॉकी एशिया कप 2025 में भारतीय टीम का प्रदर्शन ग्रुप स्टेज में उम्मीद के मुताबिक खास नहीं रहा। चीन और जापान के खिलाफ उसने जीत तो दर्ज की लेकिन प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। दोनों ही मैचों में भारत को काफी मेहनत करनी पड़ी। हालांकि, अपने आखिरी ग्रुप मैच में भारत ने कजाकिस्तान को 15–0 से हराकर शानदार जीत हासिल की और सुपर–4 में अपनी जगह पक्की कर ली। ऐसे में आज भारत का मैच कोरिया के खिलाफ होने वाला है।

हालांकि, भारत की वर्ल्ड रैंकिंग कोरिया से कहीं बेहतर है लेकिन कोरिया इस टूर्नामेंट के इतिहास की रिकॉर्ड विजेता है। 2022 का खिताब भी कोरिया के नाम ही है। उस साल सुपर–4 में भी भारत और कोरिया के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा था, जिससे भारत फाइनल से बाहर हो गया था।

हॉकी एशिया कप 2025 में कोरिया की टीम इस बार अपने बेस्ट फॉर्म से दूर दिखी है। उन्हें पूल मैच में मलेशिया ने 4–1 से हराकर झटका दिया। साथ ही कोरियाई खिलाड़ी दिन में भीषण गर्मी और उमस के कारण संघर्ष करते दिखे हैं। लेकिन सुपर–4 के मुकाबले शाम में हो रहे हैं, ऐसे में कोरिया से बेहतर खेल की उम्मीद की जा सकती है।

हेड टू हेड रिकॉर्ड

फिलहाल, भारत और कोरिया के बीच अब तक कुल 21 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से भारत ने 10 में जीत दर्ज की है, जबकि सिर्फ 2 में उसे हार मिली है। 9 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। पिछली बार एशिया कप में इन दोनों टीमों का मुकाबला 4–4 से बराबरी पर खत्म हुआ था। कोरिया ने भारत के खिलाफ आखिरी जीत 2021 में सुल्तान अजलान शाह कप के फाइनल में शूटआउट के जरिए दर्ज की थी।

एशिया कप से पहले इस खिलाड़ी को हुआ डेंगू, टीम से बाहर

नई दिल्ली 3 सितंबर। एशिया कप के लिए टीम इंडिया के 4 सितंबर को रवाना होने की खबर है. मगर उससे पहले ध्रुव जुरैल को डेंगू हो गया है. डेंगू के चलते ध्रुव जुरेल को दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है. दलीप ट्रॉफी में ध्रुव जुरेल सेंट्रल जोन के कप्तान थे. मगर अब टूर्नामेंट से हटने के बाद वो 4 सितंबर से शुरू हो रहे सेमीफाइनल मुकाबले में खेलते नहीं दिखेंगे. ध्रुव जुरेल को डेंगू होना दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल जैसे अहम मुकाबले में सेंट्रल जोन के लिए बड़े झटके से कम नहीं है.

ध्रुव जुरेल हालांकि इससे पहले दलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भी सेंट्रल जोन के लिए नहीं खेले थे. तब जुरेल को ग्रोइन इंजरी हुई थी, जिस वजह से उन्होंने खुद को मुकाबले से बाहर रखा था. दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले से पहले डेंगू होने के बाद ध्रुव जुरेल टीम से तो बाहर हुए ही हैं, साथ ही उनकी जगह विदर्भ की कप्तानी करने वाले अक्षय वाडकर को सेंट्रल जोन की टीम में शामिल किया गया है.

हालांकि, ध्रुव जुरेल को डेंगू होने से टीम इंडिया के एशिया कप अभियान पर उसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि वो उस मल्टीनेशन टूर्नामेंट में भारत की मेन टीम का हिस्सा नहीं है. ध्रुव जुरेल को रिजर्व खिलाड़ियों की लिस्ट में रखा गया था. भारत ने एशिया कप के लिए 5 रिजर्व खिलाड़ी चुने हैं. मगर उनमें से कोई भी मुख्य टीम के साथ UAE नहीं जाएगा. इन खिलाड़ियों को तभी जगह मिल सकती है, जब एशिया कप के लिए चुने 15 के स्क्वॉड में से कोई चोटिल होता है.

रजत पाटीदार (कप्तान), र्यन जुइल, दानिश मालेवार, संजीत देसाई, यश ठाकुर, आदित्य ठाकरे, दीपक चाहर, अक्षय वडकर, आ सारांश जैन, आयुष पांडे, शुभम शर्मा, यश राठौड़, हर्ष दुबे, मानव सूथार और खलील अहमद

स्टैंडबाय खिलाड़ीः महिपाल लोमरोर, माधव कौशिक, युवराज चौधरी, कुलदीप सेन और उपेंद्र यादव।

विराट कोहली ने भारत के बजाय इंग्लैंड में क्यों दिया फिटनेस टेस्ट?

नई दिल्ली 2 सितंबर। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली मैदान में लौटने को बेताब हैं. इसके लिए वो जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए उन्होंने फिटनेस टेस्ट भी पास कर लिया है, लेकिन इसमें हैरानी की बात ये है कि उन्होंने ये फिटनेस टेस्ट बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सिलेंस (COE) में न देकर कहीं और दिया है, जबकि रोहित शर्मा सहित कई खिलाड़ी ने पिछले हते COE में फिटनेस टेस्ट दिया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक अब विराट कोहली अगले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में खेल सकते हैं.

दैनिक जागरण की रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने इंग्लैंड में फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है. वो विदेशी धरती पर फिटनेस टेस्ट देने वाले मौजूदा खिलाड़ियों में से पहले क्रिकेटर बन गए हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अनुमति मिलने के बाद विराट कोहली ने इंग्लैंड में बोर्ड की निगरानी में फिटनेस टेस्ट दिया.

विराट कोहली इस समय अपने परिवार के साथ लंदन में मौजूद हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक ठब्ब् के अधिकारी के मुताबिक इंग्लैंड में फिटनेस टेस्ट देने के लिए विराट ने बोर्ड से पहले से अनुमति ली होगी. बीसीसीआई के फिजियोथेरेपिस्ट और स्ट्रेंथ एवं कंडीशनिंग कोच की टीम ने बोर्ड को सभी खिलाड़ियों फिटनेस रिपोर्ट सौंपी. इसमें कोहली की रिपोर्ट भी शामिल थी. इससे पहले टीम इंडिया के ओपनर रोहित शर्मा सहित अन्य सभी भारतीय खिलाड़ियों ने पिछले हते COE में फिटनेस टेस्ट दिया था.

इन खिलाड़ियों का भी होगा फिटनेस टेस्ट

रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, आकाश दीप और नीतीश रेड्डी इस महीने में फिटनेस टेस्ट दे सकते हैं. इनके अलावा जो खिलाड़ी चोट या बीमारी के कारण पहले दौर में ये टेस्ट नहीं दे पाए थे, वो खिलाड़ी में इसमें शामिल होंगे. इससे पहले कई खिलाड़ियों ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है.

इन खिलाड़ियों ने पास किया फिटनेस टेस्ट

रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले हते COE में रोहित शर्मा का फिटनेस टेस्ट हुआ था, जिसमें वो पास हो गए थे. इसके अलावा मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, जितेश शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, रजत पाटीदार, रवि बिश्नोई, संजू सैमसन, शिवम दुबे, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, मुकेश कुमार, हार्दिक पांड्या, सरफराज खान, तिलक वर्मा, अभिमन्यु ईश्वरन, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, ध्रुव जुरेल, शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर और यशस्वी जायसवाल ने भी फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है.

एमएलए का दामाद हुआ एशिया कप के लिए टीम इंडिया में शामिल, बीसीसीआई ने दिया बड़ा मौका

नई दिल्ली 3 सितंबर।। एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है, जिसके लिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों की रवानगी 4 सितंबर को है. खिलाड़ियों के न।म के लिए रवाना होने से पहले एक और नए सदस्य को टीम में शामिल किया गया है, जो कि एशिया कप में बड़ा रोल प्ले करते दिखेंगे. हम बात कर रहे हैं पीवीआर प्रसंथ की, जिन्हें ठब्ब् ने एशिया कप के लिए टीम इंडिया का मैनेजर बनाया है. पीवीआर प्रसंथ के पास इससे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव रहा है, जिसे देखते हुए BCCI ने उन्हें एशिया कप में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है.

अब सवाल है पीवीआर प्रसंथ हैं कौन? टीम इंडिया के नए मैनेजर बनाए गए पीवीआर प्रसंथ के बारे में दिलचस्प बात ये है कि उनका नाता एमएलए के परिवार से है. उनके पिता भी एमएलए रहे हैं और ससुर जी भी डस। हैं. इस तरह भारतीय टीम के नए मैनेजर साहब एमएलए के दामाद भी हुए.

पीवीआर प्रसंथ के पिता पुलपर्थी रामंजनेयुलु, जिन्हें अंजी बाबू के नाम से भी जाना जाता है, जो 2009 से 2014 तक विधायक रहे हैं. मार्च 2024 में उन्होंने पवन कल्याण की जनसेना पार्टी जॉइन कर ली. पीवीआर प्रसंथ के ससुर जी. श्रीनिवास राव साल 2024 में भीमली से डस। बने हैं. वो आंध्र प्रदेश के तेलगु देशम पार्टी के नेता हैं. वो आंध्र प्रदेश के मानव संसाधन और विकास मंत्री भी रहे हैं.

पीवीआर प्रसंथ के खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव और क्रिकेट करियर की बात करें तो वो आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व वाइस चेयरमैन हैं. इसके बाद वो ओल्ड वेस्ट गोदावरी टीम से जिला स्तर पर क्रिकेट भी खेल चुके हैं.

टीम इंडिया के मैनेजर का काम क्या?

अब सवाल है कि टीम मैनेजर के जिस रोल के लिए पीवीआर प्रसंथ को एशिया कप में चुना गया है. उस रोल में उनका काम क्या होगा? बतौर टीम मैनेजर वो एशिया कप के दौरान खिलाड़ियों की हर छोटी–बड़ी जरूरतों का ख्याल रखेंगे. वो BCCI और टीम के बीच पुल का काम करेंगे.

एशिया कप में भारतीय टीम के अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से हो रही है. पहला मुकाबला UAE के खिलाफ खेलने के बाद भारतीय टीम दूसरे मैच में 14 सितंबर को पाकिस्तान का सामना करेगी.

84 रन छक्के–चौके से मारे, सिर्फ इतनी गेंदों में जमाया शतक, ऐसा करने वाले तीसरे बल्लेबाज बने कृष्णा

नई दिल्ली 3 सितंबर। T20 में ताबड़तोड़ खेल का एक नजारा केरल क्रिकेट लीग में देखने को मिला. यहां 2 सितंबर को खेले मुकाबले में 26 साल के खिलाड़ी कृष्णा प्रसाद ने तूफानी शतक जड़ा. अपने तूफानी शतक में उन्होंने 84 रन सिर्फ चौके–छक्के उड़ाकर बना. अब जरा अंदाजा लगाइए कि कृष्णा प्रसाद ने कितनी बाउंड्रीज मारी होंगी. कितने छक्के लगाए होंगे और कितनी कम गेंदों पर फिर अपना शतक पूरा किया होगा? KCL 2025 में अब तक धमाकेदार शतक लगाने वाले 26 साल के .ष्णा प्रसाद तीसरे बल्लेबाज हैं. उनसे पहले संजू सैमसन समेत दो बल्लेबाज ही KCL 2025 में शतक लगा पाए हैं.

कृष्णा प्रसाद की तूफानी बल्लेबाजी

केरल क्रिकेट लीग 2025 में 2 सितंबर को अडाणी त्रिवेंद्रम रॉयल्स का मुकाबला थ्रिसुर टाइटंस से था. इस मुकाबले में रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी की थी, जिसके लिए उसके ओपनर .ष्णा प्रसाद ने धुआंधार शुरुआत की. बड़ी बात ये है कि .ष्णा प्रसाद अपनी टीम के कप्तान भी थे और जब टीम का कप्तान बल्ले के जोर पर फ्रंट से लीड करता है, बाउंड्रीज की बौछार कर शतक जड़ता है, तो फिर उससे टीम के मनोबल का अंदाजा लगाया जा सकता है.

कृष्णा प्रसाद ने बिना आउट हुए टाइटंस के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी. उन्होंने 62 गेंदों में 119 रन की नाबाद पारी खेली. 191 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से खेली इस पारी में 10 छक्के और 6 चौके शामिल रहे. मतलब कृष्णा ने छक्के से 60 रन और चौके से 24 रन मिलाकर कुल 84 रन बाउंड्रीज से बटोरे. इस दौरान कृष्णा प्रसाद ने अपना शतक सिर्फ 54 गेंदों में पूरा किया. उनकी इस पारी की बदौलत अडाणी रॉयल्स ने टाइटंस के खिलाफ 20 ओवर में 5 विकेट पर 201 रन बनाए.

17 रन से हारे टाइटंस

जवाब में 202 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टाइटंस की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 184 रन ही बना सकी और मुकाबला 17 रन से हार गई. ये KCL 2025 में अडाणी रॉयल्स की अब तक खेले 9 मैचों में दूसरी जीत रही तो वहीं टाइटंस को अपनी चौथी हार से दो–चार होना पड़ा.

तीसरे बल्लेबाज बने कृष्णा प्रसाद

केरल क्रिकेट लीग 2025 में अब तक 3 बल्लेबाजों ने शतक लगाया है, जिसमें .ष्णा प्रसाद तीसरे हैं. उनसे पहले संजू सैमसन ने 121 रन बनाए थे. जबकि अहमद इमरान ने पूरे 100 रन ठोके थे.

पाकिस्तान की हार के बाद क्या बोल गए कप्तान साहब

नई दिल्ली 3 सितंबर। एशिया कप से पहले खेली जा रही ज्20 ट्राई सीरीज में पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने जो कहा है, उसे सुनकर तरस आएगा. कप्तान साहब के मुताबिक लक्ष्य मुश्किल नहीं था. उसे हासिल किया जा सकता था. ऐसे में सवाल है कि जब सबकुछ पाकिस्तान की टीम की जद में था तो फिर टीम हारी क्यों? ये वही सलमान अली आगा हैं, जिनका चेहरा ट्राई सीरीज के पहले हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार के अफगानिस्तान को एशिया की नंबर 2 टीम बताने के बाद उतर गया था. मगर, 2 सितंबर को खेले मुकाबले में हार के बाद अब उन्हें एहसास जरूर हो रहा होगा.

सलमान आगा की अफगानिस्तान के हाथों पाकिस्तान की हार के बाद क्या कहा, आइए जरा विस्तार में जानते हैं. सलमान आगा के मुताबिक, अफगानिस्तान ने जो उनके सामने 170 रन का लक्ष्य रखा था, उसे चेज किया जा सकता था. लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि मिडिल ओवर में काफी सारे विकेट पाकिस्तान ने गंवा दिए. उन्होंने कहा कि 8वें ओवर तक तो हम अच्छा खेले. मगर उसके अगले 5–6 ओवरों में हमने काफी सारे विकेट गंवाए. सलमान आगा के मुताबिक अगर मिडिल ओवर में विकेट नहीं गिरते तो मैच का नतीजा उनके फेवर में भी हो सकता था.

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में 6 गेंदबाजों को आजमाया. लेकिन, उसमें से सिर्फ 2 ही रहे जिन्हें विकेट लेने में कामयाबी मिली. फहीम अशरफ 4 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहे तो वहीं एक और विकेट सैम अयूब ने लिया. इसके अलावा बाकी कोई भी गेंदबाज टीम को विकेट नहीं दिला सका. बावजूद इसके सलमान आगा अपने गेंदबाजों की तारीफ करते दिखे. उन्होंने माना कि उनके गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है.

पाकिस्तान की टीम एक मजाक है... अफगानिस्तान से हारकर शोएब अख्तर की बात को किया सच

नई दिल्ली 3 सितंबर। अफगानिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात में खेली जा रही T20I ट्राई सीरीज में पाकिस्तान से अपनी पिछली हार बदला ले लिया. इस सीरीज के चौथे मुकाबले में अफगानिस्तान ने अपने पड़ोसी देश को 18 रनों से हरा दिया. इससे पहले उसने UAE को हराकर इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की थी. पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अफगानिस्तान ने शानदार प्रदर्शन किया. इस दौरान उनके स्पिनर्स के आगे पाकिस्तान के बल्लेबाज टिक नहीं पाए. अफगानिस्तान से हार के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का खूब मजाक उड़ रहा है.

एशिया कप से पहले UAE T20I ट्राई सीरीज में पाकिस्तान को पहली हार का सामना करना पड़ा है. अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई. पाकिस्तान की ओर से तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने सबसे ज्यादा रन बनाए. इस दौरान सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का खूब मजाक उड़ रहा है. एक फैंस ने लिखा, "शोएब अख्तर की बात तो आपको साफ याद होगी, वो बिल्कुल सही थे. ये शारजाह की पिच थी, लेकिन जब उन्हें दुबई की पिच पर खेलना होगा, तो याद रखना, वो 130 रन भी नहीं बना पाएंगे.

एक और फैंस ने लिखा कि हमारी टीम एक मजाक है. थैंक्स मोहसिन नकवी.

दूसरे क्रिकेट फैंस ने लिखा कि अफगानिस्तान के खिलाफ दसवें नंबर के बल्लेबाज हारिस रऊफ 212.50 के स्ट्राइक रेट के साथ पाकिस्तान के शीर्ष स्ट्राइकर रहे. बाबर आजम, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा T20I रन बनाने वाले बल्लेबाज होने के बावजूद अपने पूरे T20I करियर में कभी भी यह उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए.

इस दौरान एक फैंस ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर जमकर हमला बोला. उसने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "हम बार–बार कहते रहे कि इन पिचों पर ये बेकार खिलाड़ी कारगर नहीं होंगे. टीम को बाबर आजम की जरूरत है, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी और आज अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को आसानी से हरा दिया और साबित कर दिया कि ये सारे खिलाड़ी बेकार हैं.